वर्ष 13 • अंक 22 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 13 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

कच्चे तेल, धातु में फिर से गिरावट

निर्मला सीतारमण पृष्ठ 4

बैंक विलय प्रक्रिया से कर्ज में न आए बाधा

डॉलर रु. 74.20 ▲ 60 पैसे | यूरो रु. 83.30 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) ₹ 43200 ▼ 273 रुपये | सेंसेक्स 32778.10 ▼ 2919.30 | निफ्टी 9590.20 ▼ 868.30 | निफ्टी फ्यूचर्स 9546.60 ▼ 43.60 | ब्रेंट क्रूड 32.30 डॉलर ▼ 02.20 डॉलर

कोरोना के कहर से दलाल पथ लथपथ

- बेंचमार्क सूचकांकों में 12 साल में सबसे बड़ी गिरावट
- चौतरफा बिकवाली से निवेशकों को 11.4 लाख करोड़ रुपये की चपत
- मंदड़ियों की गिरफ्त में बाजार, निफ्टी और सभी सूचकांक गिरावट के साथ बंद

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 12 मार्च

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को विश्वव्यापी महामारी घोषित करने और दुनिया भर में कोरोनावायरस का कहर बढ़ने से शेयर बाजारों में आज बहुत ज्यादा गिरावट आई। कोराना का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर से निवेशकों में घबराहट के बीच सेंसेक्स और निफ्टी 8 फीसदी से ज्यादा टूट गया और अक्टूबर 2008 के बाद इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा।

एक दिन में आई इतनी बड़ी गिरावट से निवेशकों को करीब 11.4 लाख करोड़ रुपये की चपत लगी और बहुत सारे शेयर तो कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गए। निफ्टी 868 अंक लुढ़ककर 9,590 पर बंद हुआ, जो जून 2017 के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। इसी तरह सेंसेक्स 2,919 अंक फिसलकर दो साल के निचले स्तर 32,778 पर बंद हुआ। हालिया गिरावट के बाद भारतीय बाजार भी वैश्विक बाजारों की तरह मंदड़ियों की गिरफ्त में आ गए क्योंकि अपने हाल के उच्चतम स्तर से यह करीब 20 फीसदी टूट चुका है। कोरोना के 114 देशों में फैलने और 1.18 लाख लोगों के संक्रमित होने और 4,300 लोगों की मौत से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी वजह से अधिकांश वैश्विक बाजारों में तेज गिरावट देखी गई, कुछ को तो कारोबार तक रोकना पड़ा। अमेरिकी बाजार में भी खुलते ही बिकवाली हावी हो गई और 7 फीसदी गिरने की वजह से कारोबार 15 मिनट तक के लिए रोक दिया गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशंका जताई कि प्रभावित देशों और मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं, जिससे कई देशों ने यात्रा पर रोक लगाने और अन्य सख्त कदम उठाए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने की आशंका है। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मोतीलाल ओसवाल ने कहा, 'हर कोई अनिश्चितता की बात कर रहा है और अमेरिका तथा यूरोप जैसे बाजारों में भी गिरावट बनी हुई है।' (शेष पृष्ठ 2 पर)

निफ्टी 50 की चाल

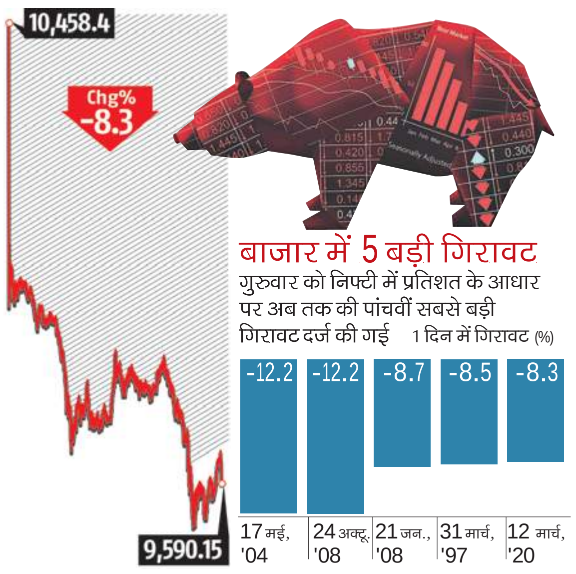

बाजार में 5 बड़ी गिरावट
गुरुवार को निफ्टी में प्रतिशत के आधार पर अब तक की पांचवीं सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई
1 दिन में गिरावट (%)

बिकवाली हावी

मंदड़ियों की गिरफ्त में बाजार

निफ्टी में शामिल कुछ शेयर और अधिकतर सूचकांक कई साल के निचले स्तर पर आ गए हैं

	भाव (~)	कितने साल के निचले स्तर पर
कोल इंडिया	155	सर्वकालिक निचले स्तर पर
ओएनजीसी	63	23 सितंबर, 2003
टाटा मोटर्स	88	21 अगस्त, 2009
आईटीसी	156	05 जून, 2012
ज़ी	191	20 नवंबर, 2012

प्रमुख सूचकांक	12 मार्च को बंद	कितने साल के निचले स्तर पर
सेंसेक्स	32,778	23 मार्च, 2018
निफ्टी	9,590	30 जून, 2017
निफ्टी मिडकैप 100	14,243	29 दिसं., 2016
निफ्टी स्मॉलकैप 100	4,671	02 मार्च, 2016
बैंक निफ्टी	23,971	23 मार्च, 2018

नकदी बचाए रखने पर जोर

जनवरी के उच्च स्तर से बीएसई सेंसेक्स में करीब 20 फीसदी की गिरावट और गुरुवार को एक दिन में करीब 8 फीसदी टूटने के बाद भारतीय शेयर बाजार मंदड़ियों की गिरफ्त में पहुंच गए हैं। पिछले दो साल में सेंसेक्स ने जितनी कमाई की थी वह हालिया गिरावट में गंवा दी। विशेषज्ञों का कहना है कि निकट भविष्य में तेज उतार-चढ़ाव बना रहेगा और निवेशक नकदी स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। घरेलू कोष प्रबंधकों का कहना है कि अगर बाजार में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले हफ्तों में फंडों से निकासी का दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे एकमुश्त निवेश से बचें क्योंकि बाजार में गिरावट की आशंका बनी हुई है। धनाढ्य निवेशक नकदी बचाकर रखना चाह रहे हैं और यह खुदरा निवेशकों के लिए भी मुफीद होगा। पृष्ठ 2

11 साल के उच्च स्तर पर वीआईएक्स

बाजार में उतार-चढ़ाव को आंकने वाला सूचकांक इंडिया वीआईएक्स साल 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार को यह 41.16 पर आ गया। इस बीच, निफ्टी में 8.3 फीसदी की गिरावट आई। वीआईएक्स से अगले 30 कैलेंडर दिनों में बाजार के सालाना उतार-चढ़ाव को लेकर निवेशकों की अवधारणा का संकेत मिलता है। लीमन ब्रदर्स के धराशायी होने के बाद वीआईएक्स 17 नवंबर, 2008 को 85.13 की ऐतिहासिक ऊंचाई को छू गया था। ट्रेडरों को देखो व इंतजार करो की रणनीति अपनानी चाहिए और ऐसे उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में उधार पर ट्रेड से दूर रहना चाहिए। पृष्ठ 2

एक नज़र

फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 6.58 फीसदी

खाद्य कीमतों में नरमी के चलते खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में धीमी पड़कर 6.58 फीसदी पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2020 में 7.59 फीसदी और फरवरी 2019 में 2.57 फीसदी पर था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2020 में खाद्य क्षेत्र की महंगाई घटकर 10.81 फीसदी रह गई जो जनवरी में 13.63 फीसदी थी। रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को तय करने में खुदरा मुद्रास्फीति एक अहम कारक है। सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति चार फीसदी से नीचे रखने का लक्ष्य दिया है।

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 2 फीसदी रही

देश की औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) की वृद्धि दर जनवरी में बढ़कर दो फीसदी पर पहुंच गई। एक साल पहले इसी महीने में यह 1.6 फीसदी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन की वजह से औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष के पहले दस माह के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटकर 0.5 फीसदी रह गई है।

दो अरब डॉलर की अदला-बदली के सौदे सोमवार को

कोरोनावायरस के भय से बाजारों में भारी गिरावट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में नकद धन का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने उपायों की घोषणा की है जिसमें मुद्रा अदला बदली के तहत दो अरब डालर के अनुबंधों की नीलामी शामिल है। अदला-बदली के तहत डॉलर के लिए अनुबंध की पहली नीलामी सोमवार को होगी। आरबीआई ने बाजार की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाने का निर्णय किया है। पृष्ठ 3

दिल्ली में कोरोना महामारी, स्कूल और सिनेमाहॉल बंद

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को विश्वव्यापी महामारी घोषित करने और देश में संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर भारत सरकार भी हरकत में आ गई है और सुरक्षा के तमाम उपाय कर रही है।

इस बीच, दिल्ली और हरियाणा की सरकारों ने कोरोनावायरस को महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और सिनेमाघरों को एहतियाती तौर पर 31 मार्च तक बंद रखने की घोषणा की है। दिल्ली में सरकारी, निजी कार्यालयों, शॉपिंग मॉलों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को संक्रमण मुक्त बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।

हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। देश भर में कोविड-19 की जांच के लिए पर्याप्त सुविधा है। देश में अब तक इसके 73 मामले सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से सजग है और लोगों को भीड़भाड़ से परहेज करना चाहिए।

■ कोरोना से संबंधित खबर : पृष्ठ 3 और 14

निजी बैंकों से रकम नहीं निकालें राज्य

येस बैंक संकट के बाद पैदा हुए हालात के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्यों से निजी क्षेत्र के बैंकों में जमा रकम नहीं निकालने का अनुरोध किया है। आरबीआई राज्यों के मुख्य सचिवों को कहा है कि सभी निजी बैंकों में जमा रकम पूरी तरह सुरक्षित है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निजी क्षेत्रों के बैंकों से रकम नहीं निकालनी चाहिए।

ऐसी खबरें हैं कि महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारों ने अपने सरकारी निकायों और अन्य इकाइयों से निजी क्षेत्र के बैंकों में रखी रकम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हस्तांतरित करने की सलाह दी है। आरबीआई ने इन खबरों के बाद राज्यों को पत्र लिखा है। आरबीआई ने कहा कि यह धारणा पूरी तरह निराधार है कि निजी बैंकों में ग्राहकों की रकम सुरक्षित नहीं है। पृष्ठ 4

खबरों में रहे स्टॉक

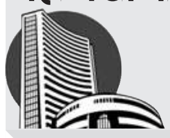

टाटा पावर कंपनी

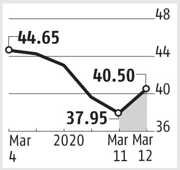

मार्च तक मुंद्रा बिजली संयंत्र को बंद रखने की योजना स्थगित

₹ 37.95 पिछला बंद भाव
₹ 40.50 आज का बंद भाव
▲ 6.72 %

आईटीसी

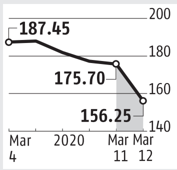

बाजार पूंजीकरण 2 लाख करोड़ के नीचे आया

₹ 175.70 पिछला बंद भाव
₹ 156.25 आज का बंद भाव
▼ 11.07 %

मदरसन सुमी सिस्टम्स

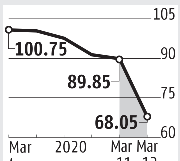

कोरोनावायरस ने वाहन क्षेत्र पर लगाया ब्रेक

₹ 89.85 पिछला बंद भाव
₹ 68.05 आज का बंद भाव
▼ 24.26 %

टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज

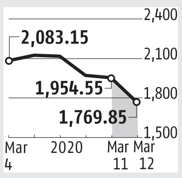

बाजार पूंजीकरण को एक ही दिन में लगा 69,306 करोड़ रुपये का झटका

₹ 1,954.55 पिछला बंद भाव
₹ 1,769.85 आज का बंद भाव
▼ 9.45 %

भारतीय स्टेट बैंक

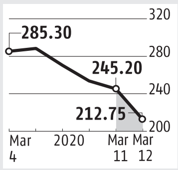

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 245.20 पिछला बंद भाव
₹ 212.75 आज का बंद भाव
▼ 13.23 %

गिरावट के बीच नकदी रखने पर रहेगा जोर

अगर शेयरों में गिरावट नहीं थमी तो आने वाले महीनों में निवेश से निकलने की प्रक्रिया जोर पकड़ सकती है

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 12 मार्च

बाजार में भीषण गिरावट के बाद एक बात साफ हो गई है कि भारतीय शेयर बाजार मंदड़ियों की गिरफ्त में आ गया है। गुरुवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 8 प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज की गई और यह जनवरी के 42,273 अंक के स्तर से 20 प्रतिशत से अधिक फिसल गया। गिरावट की मार इतनी जबरदस्त रही कि सेंसेक्स ने पिछले दो वर्षों के दौरान अर्जित बढ़त भी गंवा दी।

बाजार में मचे घमासान पर ऐक्सिस म्युचुअल फंड में इक्विटी प्रमुख जिग्नेश गोपानी ने कहा, 'मौजूदा हालात को देखते हुए निवेशक अपने पास अधिक मात्रा में नकदी रखना चाहेंगे, जिससे निकट अवधि में बाजार में अनिश्चितता बरकरार रहेगी।' वैसे घरेलू फंड प्रबंधक आने वाले दिनों में नकदी आवंटन औसतन 5 से 6 प्रतिशत बढ़ाने पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वे निकट अवधि में यह स्तर 8 से 10 प्रतिशत पहुंचने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। गोपानी का मानना है कि अगर शेयरों में गिरावट नहीं थमी तो आने वाले महीनों में निवेश भुनाने की प्रक्रिया भी जोर पकड़ सकती है।

गिरते बाजार में क्या हो रणनीति

- मौजूदा हालात को देखते हुए निवेशक अपने पास अधिक मात्रा में नकदी रखना चाहेंगे, जिससे निकट अवधि में बाजार में अनिश्चितता बरकरार रहेगी
- पर घरेलू फंड प्रबंधक आने वाले दिनों में नकदी आवंटन औसतन 5 से 6 प्रतिशत बढ़ाने पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वे निकट अवधि में यह स्तर 8 से 10 प्रतिशत पहुंचने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं

फिलहाल कुछ कहना है मुश्किल

मांग-आपूर्ति संतुलन बिगड़ने और वैश्विक फंड प्रबंधकों द्वारा बड़े पैमाने पर लिवाली करने से भारतीय शेयरों से अकेले मार्च में ही 24,000 करोड़ रुपये निवेश की निकासी हो चुकी है। कोरोनावायरस का संक्रमण लगभग पूरी दुनिया में फैलने से वैश्विक व्यापार थम सा गया है। इस वजह से दुनिया के बाजारों में निराशा का भाव छा गया है जिसके बाद वैश्विक फंड प्रबंधक तेजी से उभरते बाजारों सहित जोखिम वाली परिसंपत्तियों से निवेश निकाल रहे हैं।

गोपानी का कहना है कि फिलहाल तो विदेशी निवेशकों के रुख में बदलाव होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा,'भारतीय बाजारों में विदेश से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) के जरिये रकम आ रही थी। इन निवेशकों को जब निवेश निकालना होता है तो वे तकनीकी बुनियाद नहीं देखते हैं। तब उनका ध्यान केवल बिकवाली पर होता है।'

वैश्विक स्तर पर व्यापार सहित अन्य मोर्चों पर हालात इतने खराब हैं कि इन निवेशकों को निवेश बनाए रखने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। एक दूसरे फंड प्रबंधक ने कहा,'अमेरिका और ब्रिटेन में भी कोरोनावायरस पहुंच चुका है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होंगी।' इससे भारतीय कंपनियों की आय पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आय के आंकड़ों को किस हद तक झटका लगेगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्विटरलैंड की यूबीएस ने हाल में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी की थी।

मौजूदा हालात पर यूबीएस में अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने कहा,'हमें लगता है कि दिसंबर 2019 की सालाना 4.7 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले भारत का समायोजित जीडीपी सालाना आधार पर कम होकर मार्च एवं जून 2020 तिमाही में 4.0-4.5 प्रतिशत पर आ सकता है।'

विदेशी निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली और वृद्धि दर में कमी के अनुमानों का असर यह होगा कि भारतीय निवेशक निवेश करने के बजाय नकदी के साथ निष्क्रिय रह सकते हैं। गोपानी ने कहा,'हम निवेशकों को एकमुश्त निवेश करने बचने की सलाह दे रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि बाजार में शेयर काफी सस्ते हो गए हैं तो भी उन्हें एकमुश्त निवेश करने से बचना चाहिए।'

बीएस बातचीत

गंभीर मंदी के दौर में बाजार

भारतीय बाजार मंदी के चरण में चला गया और निफ्टी में जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से 22 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। **समी मोडक** को दिए साक्षात्कार में फर्स्ट ग्लोबल के सहसंस्थापक और वाइस चेयरमैन **शंकर शर्मा** ने कहा कि कोरोनावायरस के कारण काफी ज्यादा आर्थिक अवरोध पैदा हुए हैं और यह हर किसी को प्रभावित करेगा। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...

इतनी बड़ी गिरावट से क्या आप चकित हुए?
जनवरी में बेंचमार्क सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गए थे, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयर ही बाजार को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसी चीजें कुछ समय तक ही बनी रह सकती है और इसकी समाप्ति काफी निर्दयता के साथ होती है। इसकी समाप्ति के कुछ संकेत होंगे। भारी गिरावट की वजह कोरोनावायरस बन गया। लेकिन इस वायरस के प्रसार से पहले भी स्थिति विकट थी। साल 2000 में सिर्फ तकनीकी क्षेत्र के शेयर बाजार को आगे बढ़ा रहे थे। जब ये धराशायी हुए तो उसने पूरे बाजार को नीचे खींच लिया। साल 2007 में वित्तीय कंपनियां अच्छी चल रही थी और उनमें भी गिरावट आई। इस बार भी सिर्फ 8-9 शेयर ही बाजार को आगे बढ़ा रहे थे।

क्या हमें अभी खरीदारी पर विचार करना चाहिए?
मुझे नहीं लगता कि हमें हड़बड़ी में खरीदारी करनी चाहिए। पिछले दो दशकों में भारी मंदी का हर बाजार एक महीने में नहीं उबरा है। यह मंदी के गंभीर बाजार का पात्र बन गया है। यह सामान्य या नियमित गिरावट नहीं है। यह दुनिया भर में हो रहा है, यह भारत में हो रहा है। वायरस के कारण जितना ज्यादा आर्थिक अवरोध पैदा हो रहा है, वह शायद लंबे समय में नहीं दिखा है। ऐसे में आंख मूंदकर आगे बढ़ने और साहसी बनने की दरकार नहीं है। हमें चीजें स्थिर होने और सकारात्मक आंकड़ा आने तक इंतजार करना चाहिए। कोई चीज 20 फीसदी महंगा खरीदना उससे बेहतर है जो अगले कुछ दिनों में 30 फीसदी तक टूट जाए।

क्या ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां ज्यादा मुश्किल में होंगी?
जिन कंपनियों को बाहरी पूंजी की दरकार होती है वह हमेशा इस तरह की स्थितियों में मुश्किल में फंस जाती है। ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों के शेयर कम कर्ज वाली कर्ज फर्मों से ज्यादा टूटते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के अवरोध का असर हर कोई महसूस करेगा। कोई भी पूरी तरह से अलग नहीं रह पाएगा। झटके का स्तर आपके वित्तीय ढांचे पर निर्भर करेगा। यह व्यापक आर्थिक समस्या है, न कि किसी कंपनी विशेष या उद्योग की। कुछ लोग होंगें जिनकी स्थिति बेहतर होगी, लेकिन हर कोई प्रभावित होगा।

अभी निवेशक क्या खरीदे?
मुझे लगता है कि अभी सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियां ही सुरक्षित है।

सेंटिमेंट में सुधार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?
सरकार कई काम कर सकती है लेकिन समस्या यह है कि राजकोषीय स्थिति बहुत शानदार नहीं है। कुछ करने के लिए आपके पास वित्तीय गुंजाइश होनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट ने कुछ राहत प्रदान की है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सरकार इस पर कैसे प्रतिक्रिया जताती है।

क्या ब्याज दरों में कटौती से मदद मिलेगी?
ब्याज दरों में कटौती में समय लगेगा। यह कुंद हथियार है, न कि धारदार। ब्याज दरों में हुई हालिया कटौती का असर आर्थिक रफ्तार पर नहीं दिखा है।

टूटते बाजार में कुछ शेयरों ने दिया निवेशकों को सहारा

विश्लेषकों ने कहा, इस बाजार में मूल्यांकन के बजाय निवेशक सुरक्षा को दे रहे तवज्जो

जश कृपलानी
मुंबई, 12 मार्च

- निफ्टी-50 के चार शेयरों ने निवेशकों को कुछ राहत दी है
- इनमें नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और भारती एयरटेल शामिल हैं

बाजार में आई भारी गिरावट से परिसंपत्तियों में काफी गिरावट दर्ज हुई और 1,242 शेयरों का कारोबार 52 हफ्ते के निचले स्तर पर हुआ। 14 जनवरी को अब तक के सर्वोच्च स्तर 12,361 अंक के बाद निफ्टी में 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि इस अवधि में निफ्टी-50 के चार शेयर निवेशकों को कुछ राहत की पेशकश कर रहे हैं। इनमें नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और भारती एयरटेल शामिल हैं। इन सभी शेयरों की किस्मत वैश्विक बढ़त की रफ्तार के बजाय देसी उपभोग से जुड़ी हुई है।

मेबैंक किम इंग सिक्योरिटीज के मुख्य कार्याधिकारी जिगर शाह ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निवेशक मौजूदा माहौल में सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे हैं और अपनी रकम नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी उपभोक्ता कंपनियों में लगा रहे हैं।

एचयूएल अभी एक साल आगे की आय के 51 पर कारोबार कर रहा है जबकि नेस्ले इंडिया 70.6 पर। 14 जनवरी से नेस्ले इंडिया ने 4.7 फीसदी रिटर्न दिया है जबकि एचयूएल ने 2.35 फीसदी। एशियन पेंट्स एक अन्य शेयर है, जो चौतरफा बिकवाली के माहौल में भी टिका हुआ है। इस अवधि में इस शेयर ने 1.3 फीसदी का सकारात्मक रिटर्न दिया है।

विशेषज्ञों ने कहा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनी अपनी मजबूत बैलेंस शीट व देसी मांग पर केंद्रित होने के कारण सुदृढ़ बनी हुई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख पंकज पांडे ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था से किसी तरह का जुड़ाव रखने वाले शेयरों को बड़ा झटका लगा है। इस पर अनिश्चितता है कि वैश्विक स्तर पर कौन सा वैल्यू चेन कोरोनावायरस के प्रसार से अवरोधित हो सकता है। उन्होंने कहा, अच्छी बैलेंस शीट व देसी बाजार पर केंद्रित कंपनियों ने सुदृढ़ता दिखाई है।

साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी कंपनियों की आय के लिए सकारात्मक हो सकता है, जो उनकी इनपुट लागत का अहम हिस्सा है। जनवरी से अब तक ब्रेंट क्रूड की कीमतें 54 फीसदी घटी है।

अन्य शेयरों की बात करें तो भारती एयरटेल भारी बिकवाली के दौर में स्थिर बना हुआ है। शाह ने कहा, दूरसंचार कंपनी आठ-दस साल के कमजोर प्रदर्शन के बाद उभरी है। साथ ही दूरसंचार क्षेत्र का फंडामेंटल सुधर रहा है। टैरिफ बढ़ रहा है और एकीकरण भी हो रहा है। साथ ही ऐसे वैश्विक संकट के दौरान देश में फोन या इंटरनेट के इस्तेमाल पर शायद ही असर पड़ेगा।

डॉ. रेड्डीज लैब ने नकारात्मक रिटर्न दिया है। लेकिन निफ्टी में शामिल कंपनियों को देखें तो उसकी गिरावट न्यूनतम रही है और 14 जनवरी से अब तक यह शेयर 3.3 फीसदी टूटा है।

विश्लेषकों के मुताबिक, फार्मा कंपनियां कोरोनावायरस के प्रसार से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि इसके प्रसार के साथ दवाओं की मांग ज्यादा होगी। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोनावायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया।

ये शेयर टिके रहने में कामयाब रहे जबकि कई ब्लू चिप शेयरों पर चोट पड़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और एचडीएफसी व एचडीएफसी बैंक अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। 14 जनवरी से अब तक ये शेयर 15 से 26 फीसदी तक टूटे हैं।

एफपीआई ने निकाले 36,221 करोड़ रुपये

दीपक कोरगांवकर और पुनीत वाधवा
मुंबई/नई दिल्ली, 12 मार्च

विश्लेषकों ने कहा है कि कोरोनावायरस ने ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा असर डाला है, ऐसे में अगर विदेशी संस्थागत निवेशक जोखिम से बचना जारी रखते हैं तो भारतीय पूंजी बाजार से निवेश निकासी की रफ्तार तेज हो सकती है।

दुनिया भर में कोरोनावायरस के प्रसार के बीच सतर्क रुख अपनाते हुए विदेशी संस्थागत निवेशक पहले ही भारतीय पूंजी बाजार से पिछले 13 कारोबारी सत्र में 36,221 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं।

डाल्टन कैपिटल के प्रबंध निदेशक यू आर भट्ट ने कहा, एफपीआई, एफआईआई के लिए यह न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक जोखिम है। स्वास्थ्य को लेकर डर से दुनिया भर में निवेश की अवधारणा पर चोट पहुंची है, लेकिन पिछले कुछ सत्रों में तेल की कीमतों में हुई तेज गिरावट का फायदा भारत को नहीं मिल पाया है। कोरोनावायरस से अन्य विकसित देशों के मुकाबले भारत अपेक्षाकृत अप्रभावित रहा है। ऐसे में एफआईआई की तरफ से हो रही बिकवाली जोखिम से बचने की कवायद है। जितने लंबे समय तक यह टिका रहेगा, भारत उससे अलग नहीं रह पाएगा।

डिपॉजिटरीज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने 24 फरवरी से 11 मार्च 2020 के बीच भारतीय इक्विटी से 32,746 करोड़ रुपये (4.49 अरब डॉलर) की निकासी की है। वहीं गुरुवार को एफपीआई ने शुद्ध रूप से 3,475 करोड़ रुपये (47.1 करोड़ डॉलर) की बिकवाली की। यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों से मिली। इस तरह से शुद्ध निकासी 36,221 करोड़ रुपये रही है।

11 साल के उच्चस्तर पर इंडिया वीआईएक्स

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 12 मार्च

इंडिया वीआईएक्स साल 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया क्योंकि कोरोनावायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित किए जाने के बाद दहशत ने दुनिया भर के बाजारों पर कब्जा जमा लिया। इंडिया वीआईएक्स से ऑप्शंस की कीमत के आधार पर होने वाले तीव्र उतारचढ़ाव को लेकर निवेशकों की जोखिम की अवधारणा की माप होती है। गुरुवार को यह करीब 30 फीसदी फिसलकर 41.16 पर आ गया जबकि निफ्टी में 8.3 फीसदी की गिरावट आई। वीआईएक्स से अगले 30 कैलेंडर दिनों में बाजार के सालाना उतारचढ़ाव को लेकर निवेशकों की अवधारणा का संकेत मिलता है। जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा उतारचढ़ाव की संभावना होती है जबकि वैल्यू कम होने पर उतारचढ़ाव की संभावना कम होती है।

लीमन ब्रदर्स के धराशाही होने के बाद वीआईएक्स 17 नवंबर 2008 को 85.13 की ऐतिहासिक ऊंचाई को छू गया था। पिछले पांच वर्षों में यह 30 से नीचे रहा है। सीबीओई वॉलैटिलिटी इंडेक्स (वीआईएक्स) एक अन्य लोकप्रिय इंडेक्स है जो एसऐंडपी 500 सूचकांकों की माप करता है और यह पिछले पांच कारोबारी सत्र में 65 फीसदी उछल गया है।

विश्लेषकों ने कहा, निफ्टी के कारोबार का दायरा अब 9,000 से 11,000 के बीच

ऐंजल ब्रोकिंग के मुख्य विश्लेषक (तकनीकी व डेरिवेटिव) सुमित चौहान ने कहा, हमने पिछले 10-12 वर्षों में काफी गिरावट देखी है, लेकिन दुनिया भर में हम जिस तरह का उतारचढ़ाव और उसकी तीव्रता देख रहे हैं वह काफी असामान्य है। ट्रेडरों को देखो व इंतजार करो की रणनीति अपनानी चाहिए और ऐसे उतारचढ़ाव वाले बाजारों में उधार पर ट्रेड से दूर रहना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक, निफ्टी लगातार निचले स्तर पर बना हुआ है, जो पिछले चार हफ्तों से नजर आया है और 9500 के आसपास तेज बिकवाली नजर आई है। गुरुवार को निफ्टी 9,590 पर बंद हुआ। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के डेरिवेटिव विश्लेषक चंदन तापड़िया ने कहा, वैश्विक एक्सचेंजों में कारोबारी सत्र में 5 से 10 फीसदी का उतारचढ़ाव दिख रहा है और ट्रेडरों को निचले स्तर पर खरीदारी से दूर रहने की सलाह दी गई है क्योंकि आगामी दिनों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। निफ्टी के लिए प्रतिरोध का स्तर धीरे-धीरे घटकर 10,000 के स्तर पर जा रहा है, वहीं समर्थन का स्तर अभी 9,119 व 8,970 है। कॉल में अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 12,000 स्ट्राइक पर है और उसके बाद 10,000 स्ट्राइक पर। वहीं पुट में अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 9,500 स्ट्राइक पर है। कॉल राइटिंग 10,000 व 10,200 स्ट्राइक पर दिखा था।

बाजार में हाहाकार

पृष्ठ-1 का शेष

बाजार के भागीदारों ने कहा कि कई शेयरों का मूल्यांकन ऐतिहासिक उच्च स्तर के बाद से अब आकर्षक स्तर पर पहुंच गया है लेकिन वायरस से अर्थव्यवस्था और कंपनियों की आय पर पड़ने वाले असर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यही वजह है कि लोग बड़ा निवेश करने से परहेज कर रहे हैं। अवेंडस कैपिटल अल्टरनेट स्ट्रैटजीज के मुख्य कार्याधिकारी ऐंड्रयू हॉलैंड ने कहा, 'हर कोई इसे लेकर चिंतित है कि वायरस का प्रभाव कितना गहरा होगा। इसने बाजार की सभी सकारात्मकता को खत्म कर दिया है। कोई नहीं जानता की दुनिया में क्या हो रहा है। निवेशकों में एक तरह से डर बना हुआ है और वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।' विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी निवेशकों को आशंका है कि बाजार में और गिरावट आ सकती है। यही वजह है कि उन्हें जो भी भाव मिल रहा है, वे उसी पर बिकवाली कर रहे हैं। इससे बाजारों के पटरी पर लौटने का रास्ता लंबा हो सकता है।

विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को 3,475 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह वे पिछले 13 दिन में करीब 37,000 करोड़ रुपये भारतीय बाजारों से निकाल चुके हैं। घरेलू निवेशकों ने 3,918 करोड़ रुपये की लिवाली की। बीएसई पर ट्रेडिंग होने वाले 2,500 शेयरों में से करीब आधे शेयर एक साल के अपने निचले स्तर पर पहुंच गए। करीब 550 शेयरों पर लोअर सर्किट लगाना पड़ा और हरेक चढ़ने वाले शेयर पर करीब 23 शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। अंकों के लिहाज से यह सेंसेक्स की सबसे बड़ी गिरावट थी और उसने सोमवार की रिकॉर्ड गिरावट को पीछे छोड़ दिया। सूचकांक में भारी असर डालने वाले शेयरों जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी में करीब 8 फीसदी की गिरावट आई और इन्होंने सेंसेक्स को 1,000 अंक नीचे पहुंचा दिया। एसबीआई का शेयर सर्वाधिक 13 फीसदी टूटा जबकि ओएनजीसी के शेयर में 12.6 फीसदी की गिरावट आई। बीएसई के सभी 19 सेक्टर सूचकांकों में गिरावट आई।

खपत पर वायरस का कहर

कोरोनावायरस फैलने से उपभोक्ता एवं खुदरा बाजार पर बढ़ा दबाव

विवेट सुजन पिंटो, राघवेंद्र कामत, अर्णब दत्ता और टीई नरसिम्हन
मुंबई/दिल्ली/चेन्नई, 12 मार्च

कई कंपनियों के मुख्य अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार की वजह से भारत के कंज्यूमर एवं रिटेल बाजार पर कम से कम एक तिमाही तक दबाव झेलना पड़ सकता है। जहां आपूर्ति संबंधित चिंताएं बनी हुई हैं, वहीं कई कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चिंता घरेलू मांग पर पड़ा नकारात्मक प्रभाव है। घरेलू मांग कई तिमाहियों से कमजोर बनी हुई है।

बाजार शोध एजेंसी नीलसन के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर 2019 में एफएमसीजी बाजार ने 6 तिमाहियों में अपनी सबसे कमजोर वृद्धि दर्ज की थी। एसबीआईकैप सिक्योरिटीज में एफएमसीजी विश्लेषक नितिन गुप्ता ने कहा कि वृद्धि की रफ्तार 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कमजोर रह सकती है, क्योंकि कोरोनावायरस के मामले बढ़े हैं।

कंपनियों और विश्लेषकों का कहना है कि मांग में सुधार वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही तक दिखेगा। फिलहाल एकमात्र उत्साह स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्षेत्र में है, जिसमें कंपनियों ने पिछले कुछ सप्ताहों में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और साबुन आदि के लिए मांग में तेजी दर्ज की है। लेकिन गुप्ता का कहना है कि इससे बाजार के अन्य सेगमेंट में वृद्धि के अभाव की भरपाई नहीं हो सकेगी।

वाहन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी स्थिति अलग नहीं है। इन क्षेत्रों को कई महीनों से मंदी से जूझना पड़ रहा है। इंडिया रेटिंग्स की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू वाहन बाजार ने अप्रैल और दिसंबर 2019 के बीच बिक्री में 16 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की, जो दो दशकों में सर्वाधिक खराब स्थिति थी। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि उद्योग को वित्त वर्ष 2020 में पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले बिक्री के संदर्भ में अपने बाजार आकार में 12-15 प्रतिशत की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

दूसरी तरफ, कई प्रमुख शहरों और महानगरों में रियल एस्टेट की बिक्री 2019 में सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ी। मौजूदा कैलेंडर वर्ष के पहले तीन महीनों के लिए अनुमान कमजोर है, क्योंकि सरकार ने यात्रा और स्वास्थ्य संबंधित चेतावनियां जारी की हैं जिससे उपभोक्ताओं को बड़े आकार की खरीदारी टालने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज, मॉल और थिएटरों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश दिया है। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र की सरकारें भी सतर्क हैं, क्योंकि कोरोनावायरस के मामले इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़े हैं।

कंपनियां नुकसान और दबाव की भरपाई करने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'यह चुनौतीपूर्ण अवधि है। एफएमसीजी बाजार को खपत में मंदी से जूझना पड़ा था और अब कोरोनावायरस के डर ने स्थिति और बदतर बना दी है। वायरस से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताओं की वजह से शहरी इलाकों में लोग मॉल और स्टोरों पर नहीं जा रहे हैं। इसका शहरी इलाकों की बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा। पारंपरिक व्यापार पर भी दबाव दिखेगा।'

मुंबई की सनटेक रियल्टी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कमल खेतान ने कहा कि यदि हालात और बदतर होते हैं तो इसका रियल एस्टेट बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत में अब तक कोरोनावायरस के 73 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और इस संख्या में इजाफा होने की आशंका है।

मुंबई, दिल्ली और बेंगलूरु जैसे शहरों में रिटेलरों और मॉल मालिकों के साथ हुई बातचीत से पता चला है कि कोरोनावायरस के डर की वजह से उन्होंने ग्राहकों की संख्या में कमी दर्ज की है। सभी श्रेणियों के प्रमुख कार्यक्रमों और नई पेशकशों को टाल दिया गया है और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच भी सिर्फ टेलीविजन दर्शकों के लिए खेले जाने की संभावना है।

कोविड-19 की चपेट में बाजार

- **अक्टूबर-दिसंबर 2019 में एफएमसीजी बाजार ने 6 तिमाहियों में अपनी सबसे कमजोर वृद्धि दर्ज की थी**
- **वृद्धि की रफ्तार 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान कमजोर रह सकती है, क्योंकि कोरोनावायरस के मामले बढ़े हैं**

कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ने से ऐपल आईफोन एसई2 का लॉन्च स्थगित

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 12 मार्च

खतरनाक कोरोनावायरस कोविड-19 की रोकथाम का कोई संकेत न दिखने के मद्देनजर प्रमुख अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी ऐपल ने अपने नए आईफोन मॉडल को बाजार में उतारने की योजना फिलहाल टाल दी है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी के इस फैसले से उसके आगामी मॉडल- आईफोन एसई 2 अथवा आईफोन 9- के लॉन्च में कम से कम एक पखवाड़े की देरी हो सकती है।

आगामी हैंडसेट मॉडल के लॉन्च में देरी होने से विश्व के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में नए सिरे से खुद को स्थापित करने संबंधी कंपनी की योजना प्रभावित हो सकती है। कंपनी ने इस नए मॉडल को भारत में सबसे सस्ते आईफोन के तौर पर लॉन्च करने की योजना बनाई है जिसकी तात्कालिक कीमत 40,000 रुपये से कम रखी गई है। भारतीय बाजार के लिए अपने पिछले दांव- 2016 में आईफोन एसई का लॉन्च- की तरह इस बार भी ऐपल ने आईफोन एसई 2 को प्रवेश स्तर के आईफोन के तौर पर उतारने की योजना बनाई है। इससे कंपनी को आकांक्षी खरीदारों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोनावायरस संबंधी उथल-पुथल के कारण ऐपल की आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई है। उसके सबसे बड़ी विनिर्माता फॉक्सकॉन चीन में कोविड-19 कोरोनावायरस संकट के कारण परिचालन के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिदृश्य में नए मॉडल के लॉन्च में देरी होना तय था।

ऐपल अपने नए स्मार्टफोन मॉडल को आमतौर पर सितंबर में लॉन्च करती है लेकिन 2016 में उसने मार्च में आईफोन एसई को उतारकर सबको अचंभित कर दिया था। उसकी शुरुआती कीमत 39,000 रुपये रखी गई थी और उसके जरिये कंपनी ने उन ग्राहकों पर निशाना साधा था जो प्रीमियम हैंडसेट के लिए 50,000 रुपये से कम खर्च करना चाहते हैं। इससे पहले आईफोन 6 और 6एस शृंखला को उतारा गया था। इन मॉडलों की सफलता के कारण कंपनी की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया और देश में 32 लाख फोन की बिक्री दर्ज की गई।

सूत्रों के अनुसार, आगामी मॉडल पहले के 4 इंच लंबे मॉडल के मुकाबले कहीं अधिक बड़ा है और उसके स्क्रीन का आकार 5 इंच अथवा इससे अधिक है। अब ग्राहकों की प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं क्योंकि सस्ते डेटा के कारण वे काफी हाई डेफिनिशन वीडियो सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इसे आईफोन 6 की तरह भी डिजाइन किया गया है जो आईफोन 5एस पर आधारित आईफोन एसई से बिल्कुल अलग है।

आईडीसी के अनुसंधान निदेशक नवकेंद्र सिंह ने कहा, 'आईफोन का आगामी नया मॉडल निश्चित तौर पर भारत जैसे बाजार के लिए सही दांव है जहां ऐपल अपने महंगे उत्पाद के कारण आमलोगों के बाजार तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है। यह ऐपल के लिए काफी महत्त्वपूर्ण मॉडल है क्योंकि वनप्लस जैसे ब्रांड 30,000 से 40,000 रुपये कीमत दायरे वाले मॉडलों के साथ बाजार में पहले से ही मौजूद हैं और पिछले कुछ वर्षों के दौरान उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है।' उन्होंने कहा कि इस कीमत दायरे में आईफोन का नया मॉडल आने से ऐपल को प्रीमियम श्रेणी (35,000 रुपये से ऊपर) में भी मदद मिल सकती है।

- **मार्च के अंत में निर्धारित था लॉन्च लेकिन इस सस्ते आईफोन की योजना अब अधर में**
- **नए मॉडल का डिस्प्ले आईफोन एसई के मुकाबले बड़ा होगा**
- **डिजाइन आईफोन 8 पर आधारित है जिसमें ए13 बायोनिक चिप लगा है**
- **प्रवेश स्तर की कीमत 40,000 रुपये से नीचे रखी गई है**

इस साल के अंत में बाजार में दिखेगी तेजी: गोल्डमैन सैक्स

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 12 मार्च

डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और एसऐंडपी 500 मंदी के चरण में चले गए क्योंकि इन सूचकांकों में बुधवार को 5-5 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, ऐसे में गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों को उम्मीद है कि साल के अंत तक तेजी का नया बाजार देखने को मिलेगा।

मोटे तौर पर शेयर या इंडेक्स को तब मंदी के चरण में माना जाता है जब बेंचमार्क में 20 फीसदी तक की गिरावट आ जाती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 12 फरवरी के उच्चस्तर से 20.3 फीसदी फिसल गया है जबकि एसऐंडपी 500 में 19 फरवरी की रिकॉर्ड ऊंचाई से 19.04 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।

गोल्डमैन सैक्स के प्रमुख अमेरिकी रणनीतिकार डेविड कोस्टिन ने हालिया रिपोर्ट में कहा है, तेजी की मौजूदा बाजार की रैंकिंग इतिहास में सबसे लंबी है। इसकी शुरुआत 9 मार्च 2009 को 677 पर हुई और उसने अभी अपनी 11वीं वर्षगांठ मनाई है। तेजी का नया बाजार इस साल के अंत तक देखने को मिल सकता है।

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है, ज्यादातर निवेशकों को उम्मीद है कि कोरोनावायरस का विस्तृत प्रसार होगा, लेकिन इस पर उनकी सहमति नहीं है कि यह अवरोध कितनी लंबी अवधि तक बना रहेगा। आगे का पीई गुणक 14 गुने के बराबर होगा और एसऐंडपी 500 2,450 पर कारोबार करेगा। यह मौजूदा स्तर से 15 फीसदी और अब तक के सर्वोच्च स्तर से 28 फीसदी की गिरावट बताता है।

इस बीच वैश्विक ब्रोकिंग व रिसर्च हाउस ने एसऐंडपी 500 के आय अनुमान में और कटौती की है। 27 फरवरी को गोल्डमैन ने 2020 के लिए एसऐंडपी 500 की प्रति शेयर आय का अनुमान 174 डॉलर से घटाकर 165 डॉलर कर दिया था। अब प्रति शेयर आय में और कटौती कर उसे 157 डॉलर कर दिया गया है, जो 2019 के मुकाबले 5 फीसदी की गिरावट बताता है।

डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 12 फरवरी के उच्चस्तर से 20.3 फीसदी फिसल गया है जबकि एसऐंडपी 500 में 19 फरवरी की रिकॉर्ड ऊंचाई से 19.04 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है

बाजार में डॉलर किल्लत दूर करेगा आरबीआई

अनूप रॉय
मुंबई, 12 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बाजार में डॉलर की कमी दूर करने के लिए छह महीनों के दौरान 2 अरब डॉलर की अदला-बदली करने का निर्णय लिया है। आरबीआई की इस पहल से रुपये पर दबाव कम होगा जो रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया है।

आरबीआई सेल-बाई स्वैप करेगा यानी आरबीआई फिलहाल बाजार में डॉलर की बिक्री करेगा और छह महीने के बाद वापस खरीदारी करेगा। पिछले साल मार्च में रिजर्व बैंक ने तीन साल के लिए बाई-सेल स्वैप किया था।

आरबीआई ने अपनी बेवसाइट पर जारी एक बयान में कहा है कि दुनिया भर में बिकवाली के जबरदस्त दबाव के मद्देनजर डॉलर की अदला-बदली करने का निर्णय लिया गया है। कोरोनावायरस कोविड-19 का प्रकोप बढ़ने, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विकसित देशों में बॉन्ड प्रतिफल घटने के कारण रुपये पर दबाव बढ़ा है। अमेरिकी डॉलर के नकदी प्रवाह से तालमेल प्रभावित होने के कारण सभी परिसंपत्ति वर्ग में उतार-चढ़ाव दिख रहा है।

रिजर्व बैंक द्वारा आज शुरू की गई डॉलर अदला-बदली अन्य संभावित पहलों में से एक है क्योंकि केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल कर बाजार की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई ने कहा है कि किसी भी जरूरत से निपटने के लिए पर्याप्त मुद्रा भंडा मौजूद है। रुपया आज दिन भर के कारोबार के दौरान 74.50 रुपये प्रति डॉलर के नए स्तर तक लुढ़क गया। इससे पहले अक्टूबर 2018 में वह 74.46 रुपये प्रति डॉलर पर था।

निवेशकों ने रिजर्व बैंक से कहा- पेशकश मान लें तो वापस ले लेंगे याचिका

सुरजीत दास गुप्ता और जश कृपलानी
मुंबई, 12 मार्च

येस बैंक के अतिरिक्त टियर -1 (एटी-1) बॉन्ड के निवेशकों ने ऐक्सिस ट्रस्टी सर्विस के हवाले से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक पेशकश स्वीकार करने के बारे में लिखा है, जिससे वे कम से कम निवेश का 20 प्रतिशत पा सकते हैं। उनका कहना है कि अगर पेशकश सहमति योग्य है तो वे अपनी याचिका बंबई उच्च न्यायालय से वापस ले लेंगे।

ऐक्सिस ट्रस्टी सर्विस द्वारा रिजर्व बैंक को भेजे पत्र में कहा गया है कि बॉन्डधारकों का प्रस्ताव है कि उनकी मौजूदा देयता के एवज में उन्हें न्यूनतम 170 करोड़ शेयर उन्हें आवंटित किया जाए। इस हिसाब से प्रति शेयर 10 रुपये होने पर इसका मूल्य 1,700 करोड़ रुपये होगा और इससे करीब 20 प्रतिशत मूल बकाया मिल सकेगा।

बॉन्डधारकों ने अनुरोध किया है कि अगर इस पर कोई लॉक इन लगाया जाता है तो यह 36 महीने तक हीहोना चाहिए, जैसा कि जारीकर्ता बैंक नई इक्विटी जारी करते समय प्रस्ताव रखते हैं।

ट्रस्टी ने यह भी कहा है कि अगर उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य होती हैं तो एटी-1 बॉन्ड के ज्यादातर बॉन्डधारक, जिनके लिए ऐक्सिस ट्रस्टी काम कर रहा है, आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और मौजूदा याचिका वापस ले लेंगे।

निजी बैंकों से रकम न निकालें राज्य

अनूप रॉय
मुंबई, 12 मार्च

कुछ सरकारों ने निकायों से निजी बैंकों से धन निकालने को कहा

- आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथ ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र
- आरबीआई ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों से रकम निकालने से वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता पर हो सकता है असर
- जमा रकम की सुरक्षा को लेकर चिंता निराधार
- येस बैंक को उबारने के लिए आरबीआई उठा रहा सभी कदम
- अगर राज्यों ने निकासी का फैसला किया है तो करें पुनर्विचार

येस बैंक संकट के बाद पैदा हुए हालात के बीच भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने राज्यों से निजी क्षेत्र के बैंकों में जमा रकम नहीं निकालने का अनुरोध किया है। आरबीआई राज्यों के मुख्य सचिवों को कहा है कि सभी निजी बैंकों में जमा रकम पूरी तरह सुरक्षित है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निजी क्षेत्रों के बैंकों से रकम नहीं निकालनी चाहिए।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र का अध्ययन किया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है,'हमारा मानना है कि निजी बैंकों से राज्यों के रकम निकालने का वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।'

ऐसी खबरें हैं कि महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारों ने अपने सरकारी निकायों और अन्य इकाइयों से निजी क्षेत्र के बैंकों में रखी रकम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्थानांतरित करने की सलाह दी है। आरबीआई ने इन खबरों के बाद राज्यों को पत्र लिखा है। आरबीआई ने कहा,'हमारा मानना है कि इस तरह के कदम से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता पर असर पड़ेगा। यह धारणा पूरी तरह निराधार है कि निजी बैंकों में ग्राहकों की रकम सुरक्षित नहीं है। यह सामान्य तौर पर वित्तीय प्रणाली और विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली के हित में नहीं है।

डिप्टी गवर्नर ने पत्र में कहा,'राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई फैसला लिया है या लेने की प्रक्रिया में हैं, तो वे इस पर पुनर्विचार करें।'

आरबीआई ने कहा कि उसके पास निजी बैंकों के नियमन और निगरानी के पर्याप्त अधिकार हैं। पत्र में कहा गया है, निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रति जमाकर्ताओं का भरोसा बढ़ाने, उन्हें किसी तरह की परेशानी से बचाने के लिए येस बैंक के काम-काज पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने के बाद केंद्रीय बैंक ने उसके लिए योजना का मसौदा बिना देरी के बनाया है।

गुरुवार को कारोबार बंद होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने स्टॉक एक्सचेंजों का सूचित किया कि वह 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से येस बैंक के 725 करोड़ शेयर खरीदेगा। इस खरीदारी के बाद येस बैंक में एसबीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 49 प्रतिशत हो जाएगी।

येस बैंक में 7,250 करोड़ रु निवेश करेगा एसबीआई

अभिजित लेले
मुंबई, 12 मार्च

बैठक में फैसला

- स्टेट बैंक की बोर्ड बैठक में 10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर येस बैंक के 725 करोड़ शेयर खरीदने का फैसला

देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आज कहा है कि वह संकटग्रस्त येस बैंक में 7,250 करोड़ रुपये का निवेश कर 49 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगा। यह निवेश रिजर्व बैंक की बेल आउट योजना का हिस्सा है।

स्टेट बैंक की हिस्सेदारी निजी बैंक के पेड अप कैपिटल के 49 प्रतिशत के भीतर बनी रहेगी। स्टेट बैंक 10 रुपये प्रति शेयर के भाव 725 करोड़ शेयर लेगा।

एसबीआई ने बीएसई को बताया, 'केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की 11 मार्च को हुई बैठक में 10 रुपये प्रति शेयर की दर से येस बैंक के725 करोड़ शेयर खरीदने को मंजूरी दी गई। अभी इस सौदे को नियामकीय मंजूरियां मिलनी शेष हैं।' पुनर्गठन योजना के तहत स्टेट बैंक येस बैंक में 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदेगा और वह अपनी होल्डिंग अगले 3 साल तक 26 प्रतिशत से नीचे नहीं रखेगा।

स्टेट बैंक का 7,250 करोड़ रुपये का निवेश शुरुआत में 2,450 करोड़ रुपये निवेश कर 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की योजना से बहुत ज्यादा है। पिछले सप्ताह स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा ता कि बैंक 245 करोड़ शेयर खरीदने के लिए 2,450 करोड़ रुपये निवेश करेगा। एसबीआई अन्य निवेशकों से भी बात कर रहा है।

विलय प्रक्रिया से कर्ज में न हो बाधा

सोमेश झा
नई दिल्ली, 12 मार्च

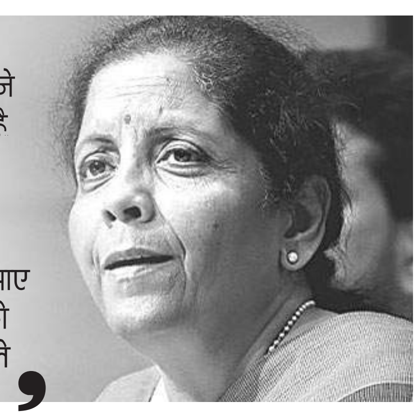

'बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि विलय की प्रक्रिया के कारण ऋण में कोई बाधा न आए और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिले'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 अप्रैल से विलय किए जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो सेट के मुख्य कार्याधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने ट्विटर पर जारी अपने वक्तव्य में कहा कि बैंको से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विलय की प्रक्रिया के कारण ऋण में कोई बाधा न आए।

विलय किए जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी तैयारियों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष एक प्रस्तुति दी। वित्तीय सेवाओं के विभाग की ओर से जारी एक वकतव्य में कहा गया, 'विलय किए जाने वाले बैंक यह सुनिश्चित करें कि ऋण में बाधा नहीं आए और ग्राहकों के अनुभव में वृद्धि हो।'

वित्त मंत्री ने आज पंजाब नैशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनियन बैंक इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के मुख्य कार्याधिकारियों से मुलाकात की। बाकी बचे बैंकों से वित्त मंत्री शुक्रवार को मुलाकात करेंगी।

बैंकों ने वित्त मंत्री के समक्ष ऋण और जमा वृद्धि तथा वर्ष वार तालमेल योजना सहित कारोबारी और वित्तीय योजनाओं का खाका पेश किया। वित्त मंत्री ने विलय किए जाने वाले बैंकों की ग्राहकों के सवालों और कठिनाइयों का सामना करने और समाधान करने की तैयारियों और क्षमताओं का आकलन किया।

1 अप्रैल से पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी), ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मिलकर देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।

केनरा बैंक में सिंडीकेट बैंक का विलय किया जाएगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आंध्रा बैंक तथा कॉर्पोरेशन बैंक के साथ विलय किया जाएगा और इंडियन बैंक में इलाहाबादा बैंक का विलय होगा। अप्रैल से इन बैंकों के बही खातों और स्टॉकों का विलय हो जाएगा।

नकदी बढ़ाने के कदम उठा सकता है रिजर्व बैंक

रॉयटर्स
नई दिल्ली, 12 मार्च

भारत का केंद्रीय बैंक वित्तीय बाजारों को स्थिर होने में मदद करने के लिए नकदी बढ़ाने के कदमों की घोषणा कर सकता है। एक सूत्र ने आज यह जानकारी दी। कोरोनावायरस के कारण इस समय बाजार तेजी से गिरा है। भारत का शेयर बाजार लुढ़कर गुरुवार को बहुत नीचे चला गया। कोरोनावायरस को आपदा घोषित किए जाने के बाद निफ्टी-50 गिरकर ढाई साल के निचले स्तर पर है और अमेरिका ने यूरोप से आवाजाही रोक दी है। निफ्टी 50 और एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स 6 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर बंद हुए जो 7.5 प्रतिशत से ज्यादा नीचे चले गए थे। बाजार उम्मीद कर रहा है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करेगा, लेकिन सूत्रों ने कहा कि फिलहाल इस समय ऐसे किसी कदम पर विचार नहीं किया जा रहा है।

एक और अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। सूत्र ने कहा, 'रिजर्वैंक बाजार में और ज्यादा नकदी डालने और उन क्षेत्रों के पुनर्भुगतान मसलों को सरल करने पर विचार कर रहा है, जहां आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है।' भारत की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 31 मार्च को होनी है। दोनों अधिकारियों ने कहा कि इसके पहले दरों के बारे में फैसला किए जाने की संभावना नहीं है। पिछले कुछ महीने के दौरान खुदरा महंगाई दर में तेज बढ़ोतरी की वजह से इस साल रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में कटौती नहीं कर सका है।

जेट के लिए मांगा जा सकता है वक्त

सुब्रत पांडा
मुंबई, 12 मार्च

नया फैसला

- जेट एयरवेज के कर्जदाता एनसीएलटी से समाधान के लिए 90 दिन का मांग सकते हैं वक्त
- कर्जदाताओं का मानना है कि वैश्विक मंदी को देखते हुए अभी परिसमापन का सही वक्त नहीं

जेट एयरवेज के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने आज फैसला किया है कि वह एयरलाइंस के कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआरआईपी) में एक विस्तार के लिए आवेदन करेगी क्योंकि कंपनी के पुनरुद्धार की कोई योजना नहीं बन सकी है और इसका समर्थन करने के लिए कोई कारोबारी अभी योजना पेश नहीं कर सका है।

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से 90 दिन का वक्त मांगा जा सकता है।

इसके अलावा बैठक में यह भी चर्चा हुई कि संभवत: यह कंपनी के परिसमापन के लिए सही वक्त नहीं है क्योंकि कोरोनावायरस की अफरातफरी के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर है।

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत सीआईआरपी के लिए अधिकतम समय 330 दिन तय किया गया है, जिसमें याचिका की अवधि भी शामिल होती है। कंपनी के लिए सीआरआईपी के 270 दिन 15 मार्च को पूरे होने वाले हैं।

आईबीसी प्रावधानों के तहत जेट एयरवेज दिवाला न्यायाधिकरकण से 60 दिन का विस्तार ले सकती है। बहरहाल यह एनसीएलटी पर निर्भर है कि कोई भी कंपनी समाधान की योजना पेश नहीं कर सकी है, इसे देखते हुए वह 90 दिन विस्तार की अनुमति देता है या नहीं। जेट के लिए समधान योजना पेश करने की अंतिम तिथि बीतने तक पुनरुद्धार की कोई योजना नहीं मिली है, जो 9 मार्च को खत्म हो चुकी है।

सूत्रों ने कहा कि तीन कारोबारी- रूस की फार ईस्ट डेवलपमेंट फंड, नई दिल्ली की प्रूडेंट एआरसी और दक्षिण अमेरिका की सिनर्जी ग्रुप अभी भी कतार में हैं, लेकिन स्लॉट से जुड़ा मसला बड़ा व्यवधान है, जो उन्हें समाधान योजना पेश करने से रोक रहा है। साथ ही कुछ और भी चिंताएं हैं।

रूस के फंड ने पिछले महीने एयरलाइन के पुनरुद्धार में दिलचस्पी दिखाई थी और उम्मीद की थी कि भारत के बाजार में सुखोई सुपर जेट 100 उतारा जाएगा। इसके अधिकारियों ने केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, लेकिन कंपनी ने एयर इंडिया में निवेश पर विचार नहीं किया।

वहीं प्रूडेंट एआरसी ने निवेशकों से धन जुटाने के लिए अतिरिक्त वक्त की मांग की थी, लेकिन वह कोई योजना पेश नहीं कर सकी।

वहीं सिनर्जी समूह ने एयरपोर्ट भारत व विदेश में स्लॉट के मामले को लेकर सुस्ती दिखाई, साथ ही समूह ने जेट की पिछली देनदारियों को लेकर भी सवाल उठाए थे।

संक्षेप में

चालू खाते का घाटा घटकर 1.4 अरब डॉलर हुआ

देश का चालू खाते का घाटा चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घटकर 1.4 अरब डॉलर पर आ गया। रिजर्व बैंक के बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.2 प्रतिशत के बराबर है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा जीडीपी के 2.7 प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष की इससे पिछली तिमाही में जीडीपी का 0.9 प्रतिशत था। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक चालू खाते के घाटे में आई गिरावट की वजह व्यापार घाटे का नीचे आकर 34.6 अरब डॉलर रहना और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि होना है। *भाषा*

बैंकों का ऋण 6.13 और जमा 9 प्रतिशत बढ़ा

बैंकों का ऋण 28 फरवरी को समाप्त पखवाड़े में 6.13 प्रतिशत बढ़कर 101.04 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इस दौरान बैंकों में जमा राशियां 9 प्रतिशत बढ़कर 133.31 लाख करोड़ रुपये रहीं। *भाषा*

मध्य प्रदेश में सरकार बचाने का संघर्ष जारी

बीएस संवाददाता
भोपाल, 12 मार्च

संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'सिंधिया जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उनकी विचारधारा को जानता हूं। वह मेरे साथ कॉलेज में थे। उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर डर लगा। उन्होंने अपनी विचारधारा को जेब में डाल दिया और आरएसएस के साथ चले गए।' उन्होंने कहा, 'वास्तविकता है कि उन्हें वहां सम्मान नहीं मिलेगा। वह समझ जाएंगे। उनके दिल में जो है और मुंह से जो निकल रहा है, वो अलग अलग चीज है।' *फोटो-पीटीआई*

कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद भी मध्य प्रदेश का राजनीतिक संकट जल्द समाप्त होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस प्रदेश में अपनी सरकार बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह बागी विधायकों को मनाने बेंगलूरु गए जहां स्थानीय पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। एक बागी विधायक मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी भी उनके साथ थे।

कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह विशेष योजना के साथ बेंगलुरु में मौजूद 9-10 बागी विधायकों को निकालने में सफल हो गए थे। परंतु ऐन वक्त पर भाजपा के दबाव में काम कर रही पुलिस उन्हें हिरासत में ले लिया।

बाद में पटवारी ने कहा, 'कुछ विधायक हमसे मिलना चाहते थे। मेरे चचेरे भाई मनोज चौधरी भी यहां हैं। मैं अपने भाई से मिलने आया था लेकिन हमें रोका गया। हम अपने मित्रों से मिलना चाहते हैं। क्या यह गुनाह है? इन विधायकों ने 15 साल संघर्ष किया है। उन पर दबाव डालकर उनके फोन ले लिए गए। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सिंधिया राज्य सभा जाएंगे, मंत्री बनेंगे लेकिन इस्तीफा देने वाले विधायकों का क्या होगा?'

इससे पहले कांग्रेस के राज्य सभा सदस्य विवेक तन्खा ने कहा कि मनोज चौधरी अपने पिता के साथ वापस आना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं आने दिया गया। उन्होंने कर्नाटक पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, 'इन दोनों मंत्रियों जीतू पटवारी और लाखन सिंह के साथ बेंगलुरू पुलिस ने मारपीट की और उन्हें हिरासत में लिया।' उधर दिग्विजय सिंह ने भाजपा से लोकतंत्र को खतरा होने के आरोप लगाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए भाजपा अब 'ऑपरेशन लोटस' नहीं चला रही है, अब वह 'ऑपरेशन मनीबैग' हो गया है।

मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने गुरुवार को 22 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर उपस्थित होने को कहा है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की ओर से राज्यसभा की सदस्यता का नामांकन दाखिल किया तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा में जाने के बाद राजधानी में पहला रोड शो किया। वह शुक्रवार को नामांकन करेंगे।

11 महीने बाद वाहनों की खुदरा बिक्री में सुधार

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 12 मार्च

आई थोड़ी खुशी

यात्री वाहनों को छोड़ दें तो फरवरी में करीब 11 महीने बाद वाहनों की खुदरा बिक्री में सुधार हुआ है। डीलरों का कहना है कि कुल खुदरा बिक्री की सालाना आधार पर वृद्धि दर उम्मीद से बहुत कम है क्योंकि बीएस-4 वाहनों की अनुमानित खरीद नजर नहीं आ रही है।

कुल मिलाकर वाहनों की बिक्री जहां 2.6 प्रतिशत बढ़ी है, यात्री वाहनों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस फरवरी में 1.17 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह एकमात्र क्षेत्र है, जहां सुस्ती देखी गई, क्योंकि ग्राहक अपने खरीद के फैसले टाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 31 मार्च के नजदीक बेहतर छूट मिलेगी, जब बीएस-5 की ओर बढ़ने की अंतिम तिथि है।

तिपहिया वाहनों की बिक्री फरवरी 2020 में बढ़कर 65,752 हो गई जो फरवरी 2019 में 54,474 थी। इसमें 20.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ट्रैक्टरों की बिक्री 13.53 प्रतिशत बढ़कर 36,543 से 41,485 हो गई है। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 13 प्रतिशत बढ़ी है और यह 82,129 से बढ़कर 92,805 हो गई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री 1.52 प्रतिशत बढ़ी है और पिछले साल फरवरी की 12,66,163 यूनिट से बढ़कर फरवरी 2020 में इसकी बिक्री 12,85,398 यूनिट हो गई है। यात्री वाहनों की बिक्री में 1.17 प्रतिशत की कमी आई है। फरवरी 2020 में 2,26,271 वाहनों की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल फरवरी में 2,28,959 वाहनों की बिक्री हुई थी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 22

कोरोनावायरस का प्रभाव

सरकार ने कोरोनावायरस के प्रसार को लेकर सहज और समझदारी भरी प्रतिक्रिया दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे विश्वव्यापी महामारी घोषित कर दिया है। ऐसे में लग रहा है कि भारत इस बीमारी के अत्यधिक हानिकारक प्रभाव से बच जाएगा। सरकार ने दुनिया भर के देशों के पर्यटक वीजा पर रोक लगा दी है और प्रवासी भारतीयों के वीजा मुक्त प्रवेश पर भी 15 अप्रैल तक रोक लगा दी है। उसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे एपिडेमिक डिजीज ऐक्ट के प्रावधान लागू करें। सन 1897 में बना यह कानून राज्यों को बीमारी का प्रसार रोकने के लिए मौजूदा कानून निलंबित करने और अस्थायी उपाय अपनाने की अनुमति देता है। अधिनियम केंद्र को यह इजाजत भी देता है कि वह बंदरगाह पर किसी पोत की जांच कर सके। चूंकि यह कानून 122 वर्ष पुराना हो चुका है ऐसे में बेहतर होगा कि इसमें शीघ्र संशोधन कर ये जांच अधिकार विमानों पर भी लागू किए जाएं। हवाई अड्डों पर हो रही स्वास्थ्य जांच और टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से जनहित में नियमित संदेश प्रसारण भी यह दिखाते हैं कि सरकार इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए अति सक्रिय है। इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर जारी अनिश्चितता भी शीघ्र समाप्त होनी चाहिए। विकल्प एकदम स्पष्ट हैं या तो इसे बंद और सुरक्षित स्थान पर अंजाम दिया जाए या फिर रद्द किया जाए।

बहरहाल बड़ी चुनौती जानी अनजानी बातों में छिपी हुई है। इनमें प्रमुख है इस बीमारी का दायरा और इसके बारे में जानकारी। डेढ़ महीने पहले तीन जाहिर मामलों के बाद तीन दिन पहले यह आंकड़ा 68 और गुरुवार को 73 तक पहुंच गया। यह तादाद बढ़ाने में इटली के पर्यटकों की अहम भूमिका रही। परंतु सूचना का प्रसारण अस्पष्ट बना हुआ है। लेह में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह पुष्टि होनी बाकी है कि उसकी मौत कोरोनावायरस से हुई या किसी अन्य बीमारी से। इसके अलावा देश की मौजूदा स्थिति की बात करें तो सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब है और शहरी बस्तियों और झुग्गियों आदि में इसे लेकर जागरूकता का सख्त अभाव है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं कि बीमारी को किस हद तक थामा जा सकता है। बचाव के दो प्रमुख उपाय यानी नियमित अंतराल पर हाथ धोना और सामाजिक रूप से दूरी बनाकर रहना भी अस्पष्ट हैं और इनका प्रवर्तन करना कठिन है। खासकर कम शिक्षित और गरीब तबकों में। उदाहरण के लिए हवाई यात्राओं में कमी आ सकती है और प्रभावशाली शहरी भारतीय घर से काम कर सकते हैं लेकिन लाखों दैनिक श्रमिकों को भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक यातायात से गुजरकर ही इस आर्थिक मंदी के बीच अपनी आजीविका जुटानी है। चूंकि कोरोनावायरस के लक्षण फ्लू जैसे हैं इसलिए यह निश्चित नहीं कि इसके पीड़ितों में कितने लोग वास्तव में पहचाने जाएंगे। एक सवाल यह भी है कि क्या देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली इस चुनौती के लिए तैयार है। गौरतलब है कि देश में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। देश भर में बने 52 परीक्षण केंद्र भी अपर्याप्त नजर आते हैं। पर्यटकों की भारी आवक वाले उत्तर प्रदेश में केवल तीन परीक्षण केंद्र बने हैं।

इसकी आर्थिक कीमत भी चुकानी होगी। वैश्विक व्यापार में मंदी और रोजगार की मांग वाले क्षेत्रों में मांग घटने से देश की पहले से कमजोर वृद्धि और कमजोर होगी। तेल कीमतों में गिरावट से कुछ राहत अवश्य मिल सकती है। कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता भी गतिरोध उत्पन्न करेगी। शेयर बाजार में मची भगदड़ इसकी बानगी है। ऐसे में सरकार के पास अवसर है कि वह कड़े आर्थिक सुधार अपनाकर देश को वृद्धि पथ पर वापस लाए।

अजय मोहंती

पारिस्थितिकी संकट का संकेत है कोविड-19

इस संकट को अलग-थलग मानकर उससे निपटने की योजना काम नहीं करेगी। इसके लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इस बारे में बता रहे हैं **श्याम सरन**

कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी का पूरी दुनिया में प्रसार जारी है और यह पहले ही विकराल स्वास्थ्य संकट बन चुका है। अब इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालना शुरू कर दिया है जिससे उत्पादन, यात्रा और व्यापार की व्यवस्थाएं तार-तार हो रही हैं। संभव है कि एक साल के भीतर इसका प्रभावी टीका विकसित किया जा सकता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी और यह एक विकट महामारी का रूप ले चुकी होगी।

इस संकट से निपटने के लिए इसके गहरे निहितार्थ पर विचार करने की जरूरत है। कोविड-19 एक व्यापक पारिस्थितिकी संकट का लक्षण है जिससे मानव अस्तित्व के लिए खतरा है। इसके कई कारण हैं। जैव विविधता की कीमत पर प्रजातियों के मानकीकरण पर आाधारित कृषि और पशुपालन का औद्योगीकरण बढ़ता जा रहा है। वन्य प्राणियों का प्राकृतिक पर्यावास सिकुड़ता जा रहा है जिससे वे इंसानी बस्तियों में आ रहे हैं। साथ ही इंसानों का अनजाने में ही सही, ऐसे जीवों के संपर्क हो रहा है जिनसे बचने में लिए उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। इन्हीं सबका अपरिहार्य नतीजा हमारे सामने कोविड-19 के रूप में मौजूद है। शहरों में आपको लूटपाट करने वाले बंदरों की टोलियां दिखाई देती हैं। तेंदुए और हाथी अक्सर गांवों और शहरी इलाकों में घुस आते हैं क्योंकि जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। भारी मात्रा में उत्पादन की औद्योगिक तकनीकों के कारण यह स्थिति आ गई है कि बड़ी संख्या में मुर्गियों और पशुओं को तंग जगहों पर रखा जाता है। इस तरह अगर एक जानवर को भी संक्रमण होगा तो वह बहुत तेजी से फैलेगा। स्वाइन फ्लू और एवियन फ्लू इसके उदाहरण हैं। सूअरों और मुर्गियों से यह बीमारी फिर इंसानों में आती है। इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए जानवरों को नियमित रूप से एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। यह एंटीबायोटिक्स फिर खाद्य शृंखला में आ जाता है और इंसानी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है। कृषि और पशुपालन के औद्योगीकरण ने भले ही खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया है लेकिन यह स्वास्थ्य सुरक्षा में एक नकारात्मक फीडबैक लूप बनाता है।

सच्चाई यह है कि आज इंसान को कई मोर्चों पर संकट का सामना करना पड़ रहा है जैसे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, पानी की कमी, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता शामिल है। ये सभी संकट एकदूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। कभी-कभी पारस्परिक रूप से एकदूसरे को मजबूत करते हैं और अभी एकदूसरे का प्रभाव कम करते हैं। ये हमारी जीवनशैली, मूल्यों, अतीत की हमारी समझ और भविष्य की आकांक्षाओं से जुड़ी गहरी सभ्यतागत खामियों के लक्षण हैं। हर संकट को अलग मानकर उससे निपटने की योजना काम नहीं करेगी क्योंकि फीडबैक लूप के जरिये उसका दायरा बहुत व्यापक है। कोविड-19 जैसा संकट हमारे ग्रह की पारिस्थितिकी का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन संभव है कि इसका संबंध दूसरे क्षेत्रों में हो रही घटनाओं से हो सकता है। हालांकि इसका असर तुरंत देखने को नहीं मिल सकता है। यहां एक अंतरनिर्भर आकस्मिक शृंखला काम कर रही थी। कोविड-19 विषाणु अमूमन जंगल में रहने वाले जीवों में रहता है। इस मामले में यह जंगली चमगादड़ से आया है। ये चमगादड़ चीन में वुहान के खाद्य बाजार में रखे गए जानवरों के संपर्क में आया जिससे इनके प्रसार का खतरा बढ़ गया। इन जानवरों को औद्योगिक रूप से तैयार किया गया था। खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर परिणाम की परवाह किए बिना विकसित की गई इन प्रक्रियाओं में यह जोखिम अंतर्निहित है। चुनौतियों को व्यापक परिपेक्ष्य में नहीं देख पाने की हमारी कमजोरी मौजूदा ज्ञान व्यवस्थाओं में अंतरनिहित है जो स्पेशलाइजेशन के बढ़ने और व्यापक परिदृश्य पर जोर देने से लगातार बढ़ रहा है। इसकी बड़ी तस्वीर पृथ्वी की नाजुक पारिस्थितिकी को साथ बांधने वाली असंख्य कड़ियों की जानकारी है। पारिस्थितिकी के एक हिस्से में छोटी सी हलचल दूसरे हिस्सों में व्यापक तबाही ला सकती है। लेकिन यह सच्चाई तेजी से अस्पष्ट हो गई है और सामूहिक अंधेपन के आवेश में इसे नकारा जा रहा है। इसका कारण खोजना मुश्किल नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करने का मतलब होगा कि हमें अपनी जीवनशैली में बदलाव करना होगा, अपने मूल्यों को बदलना होगा और इंसानियत को प्रकृति से जोड़ना होगा। मानव प्रकृति है, न कि मानव प्रकृति के खिलाफ है जो कि औद्योगिक दौर का मूलमंत्र रहा है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी समिति की रिपोर्ट में पेरिस समझौते में शामिल आकांक्षी लक्ष्यों के प्रभावों की समीक्षा की गई है। इस समझौते में धरती के तापमान में वृद्धि को औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की तुलना में केवल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम पहले ही 1.5 डिग्री की सीमा पर पहुंचने के कगार पर हैं और जलवायु उथलपुथल के लिए इतना ही काफी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में बल्कि समाज में भी कायाकल्प की जरूरत होगी। सभ्यतागत प्रतिक्रिया को प्रभावित किए बिना सामाजिक बदलाव संभव नहीं है।

हम प्रौद्योगिकी के दौर में रह रहे हैं। यह एक व्यापक धारणा है कि प्रौद्योगिकी हमारे समक्ष मौजूद संकटों का कुछ न कुछ समाधान ढूंढ लेगी और इसके लिए हमें अपनी जीवनशैली में बदलाव नहीं करना पड़ेगा। कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग की नई दुनिया आने को तैयार है। क्वांटम कंप्यूटिंग और जेनिटिक इंजीनियरिंग में चमत्कार हो रहे हैं। भविष्य की प्रौद्योगिकी प्रगति के नतीजे इंसान पर बहुत हावी हो सकते हैं।

यह हो सकता है। लेकिन क्या हमारा ग्रह और पृथ्वी पर जीवन प्रौद्योगिकी के इस चमत्कार को देखने के लिए जिंदा बचेंगे? उदाहरण के लिए क्या यह संभव नहीं है कि कोई विषाणु उसका टीका विकसित होने से पहले ही दुनिया की आबादी को खत्म कर दे? शायद कोविड-19 पारिस्थितिकी आपदा के लिए खतरे की घंटी है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं।

पारिस्थिकीय संकट से निपटने के लिए इंसान की योजना क्या होनी चाहिए? हमें प्रकृति को एक जीवित स्रोत की तरह देखना चाहिए और उसका उतना दोहन नहीं करना चाहिए कि उसका अस्तित्व की खतरे में पड़ जाए। पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जैवविविधता बुनियादी जरूरत है और इसका हर हाल में संरक्षण होना चाहिए।

हम जिस तरह एकदूसरे को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसके लिए वैश्विक स्तर पर एक व्यापक और समन्वित योजना की जरूरत है। अधिकारप्राप्त अंतरराष्ट्रीय संचालन संस्थाओं के जरिये चलने वाली बहुस्तरीय प्रक्रियाओं का कोई विकल्प नहीं है।

सबसे अहम बात यह है कि हमें समृद्धि की एक नई परिभाषा की जरूरत है जो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए ताजा पानी और घूमने के लिए हरी भरी पृथ्वी को अहमियत दे।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव और सीपीआर में सीनियर फेलो हैं। 2007 से 2010 तक वह जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत थे।)

राज्यों के बजट पर अधिक ध्यान देने की है जरूरत

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

हर वर्ष आम बजट पेश होने के बाद इसमें किए गए वित्तीय आवंटन और नीतिगत पहलों पर तमाम बहस और चर्चा होती है। यह वांछित भी है। गत माह प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के बजट पर भी यह बात लागू होती है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट पर अर्थशास्त्री और टीकाकार उतना ध्यान नहीं देते। यह दिक्कत की बात है। उदाहरण के लिए 2019 में 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का अनुमानित बजट 37 लाख करोड़ रुपये रहा। यह वर्ष के 27 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट से 37 प्रतिशत अधिक था। राज्यों के बजट की ऐसी अनदेखी ठीक नहीं। यह अनदेखी शायद सरकारों के वार्षिक वित्तीय वक्तव्य जारी करने के तरीके से संबंधित है। सभी राज्य सरकारों के वित्तीय आवंटन संबंधी वक्तव्य में एकरूपता नहीं होतीं। ऐसे में इन वित्तीय वक्तव्यों का विश्लेषण कठिन और हताश करने वाला होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक सभी राज्यों के बजट का वार्षिकसार-संक्षेप पेश करता है लेकिन यह काफी देर से आता है। बीते कुछ सप्ताह में नौ राज्यों ने अपना सालाना बजट पेश किया। ये राज्य है बिहार, हरियाणा, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सन 2019-20 में इन राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद करीब 93 लाख करोड़ रुपये रहा जो देश के जीडीपी का 45 प्रतिशत से ज्यादा है।

इसके बावजूद इन बजट का समुचित विश्लेषण मीडिया में नहीं हुआ। इन राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा बजट पेश करने के बाद अहम घोषणाओं को मीडिया में स्थान दिया गया। बहरहाल, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने इन बजटों में शामिल प्रमुख वित्तीय आंकड़ों को एकीकृत ढंग से पेश करके अच्छा किया है। इससे इनका विश्लेषण आसान हुआ है।

ये नौ बजट क्या दर्शाते हैं? चिंता की बात है कि राज्य बजट आंकड़ों की मजबूती और उनकी ईमानदारी भी केंद्रीय बजट के आंकड़ों की तरह कमजोर हुई है। 2019-20 के बजट के संशोधित अनुमानों की पिछले अनुमान से तुलना करने पर यह जाहिर हुआ। आम बजट में भी बजट अनुमान और संशोधित अनुमान का अंतर लगातार बढ़ रहा है। यदि इस वर्ष अब तक पेश नौ राज्यों के बजट को संकेत मानें तो यह बीमारी राज्यों में भी फैल गई है।

उदाहरण के लिए 2019-20 में सभी नौ राज्यों का बजट संशोधित अनुमान पहले जताए गए अनुमानों से काफी भिन्न-भिन्न था। उत्तर प्रदेश में संशोधित अनुमान पूर्व में लगाए अनुमान से 5.8 फीसदी कम था। राजस्थान, पंजाब ओडिशा और हरियाणा में भी यही रुख देखने को मिला और वहां इसमें 3.5, 4.3, 2.9 और 2.1 फीसदी गिरावट आई।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिन राज्यों में संशोधित अनुमान पहले से ज्यादा रहा उन सभी में एक साल में चुनाव होने थे। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के अंत में होने हैं। वहां यह व्यय 8.6 फीसदी ज्यादा रहा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 2021 के आरंभ में विधानसभा चुनाव होना है उनका संशोधित अनुमान 4.3 और 2.2 फीसदी ज्यादा है। लेकिन केरल जहां 2021 में ही चुनाव होने हैं, वहां संशोधित अनुमान 11 फीसदी कम हुआ।

अब तक पेश इन नौ राज्यों के बजट में दो अन्य रुझान ध्यान देने लायक रहे। संशोधित अनुमान में हर राज्य की प्राप्तियों में कमी आई। यह व्यापक तौर पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) संग्रह में आई कमी की वजह से हो सकता है। परंतु राजस्व अनुमान को व्यवहार्य स्तर से अधिक बताना बजट अनुशासन को भंग कर सकता है और इससे राज्य की व्यय प्रतिबद्धताएं पूरी करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

बिहार में संशोधित अनुमान के अधीन प्राप्तियां बजट अनुमान से 14.3 फीसदी कम रहीं। केरल में यह 14 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 5.4 फीसदी, हरियाणा में 5.2 फीसदी, पंजाब में 4.4 फीसदी, राजस्थान में 4.3 फीसदी, ओडिशा में 2.8 फीसदी और तमिलनाडु में 2.7 फीसदी की कमी आई। पश्चिम बंगाल की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही और उसका संशोधित अनुमान बजट अनुमान की तुलना में 0.6 फीसदी ही कम रहा।

अधिकांश राज्यों के अपने राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति से इतना दूर रहने के बावजूद सन 2020-21 में राज्यों के बजट काफी महत्त्वाकांक्षी हैं और इनमें अगले वर्ष की प्राप्तियों के लिए दो अंकों का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार में 2020-21 में प्राप्तियों में 21.5 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया है। केरल में 15.6 फीसदी, तमिलनाडु में 13.9 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 13 फीसदी, ओडिशा और पंजाब में 11 फीसदी तथा पश्चिम बंगाल में प्राप्तियों में 10 फीसदी इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि पंजाब और राजस्थान में यह रुझान उलटा है। पंजाब में अगले वर्ष प्राप्तियों में 2.2 फीसदी की कमी आने की बात है जबकि राजस्थान में यह महज 0.2 फीसदी बढ़ेगी।

दूसरा परेशान करने वाला रुझान यह है कि कई राज्यों पर कर्ज अदायगी का बोझ बढ़ता जा रहा है जो जीएसडीपी के 3 फीसदी के ऊपर है। पंजाब के लिए यह जीएसडीपी का 10.8 फीसदी, केरल के लिए 7.13 फीसदी, पश्चिम बंगाल के लिए 6.28 फीसदी, हरियाणा के लिए 4.48 फीसदी, राजस्थान के लिए 4.29 फीसदी तथा उत्तर प्रदेश के लिए 3.55 फीसदी के स्तर पर है। केवल तमिलनाडु ने एसजीडीपी के 2.67 फीसदी स्तर के साथ ऋण अदायगी को नियंत्रण में रखा है। वर्ष 2019-20 में केंद्र की ब्याज देनदारी जीडीपी के 3 फीसदी के बराबर थी। यह संभव है कि शेष 22 सरकारों (राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश) द्वारा आने वाले दिनों में पेश किया जाने वाला बजट एक अलग तस्वीर पेश कर सकता है। परंतु नौ राज्यों के बजट में देखने को मिल रहे रुझानों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। संक्षेप में कहें तो राज्यों के बजट पर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

कानाफूसी

सांसदों में भी कोरोना का खौफ

कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में चौतरफा कड़े उपाय अपनाए जा रहे हैं। संसद भवन भी इससे अछूता नहीं है और देश के सांसद भी इससे बचने के लिए हरसंभव उपाय अपना रहे हैं। कई सांसदों ने होली के त्योहार से दूर रहने का निर्णय लिया जबकि यह त्योहार उनके लिए अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने का अवसर लाता है। इतना ही नहीं सांसदों को संसद में उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर के दौरान एक दूसरे के पेन साझा करने से बचते देखा गया। संसद परिसर के अलावा भी कई सांसद मास्क पहन रहे हैं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सांसद तो वाइप से अपने मोबाइल फोन को साफ करते देखे गए क्योंकि इन फोनों का इस्तेमाल उनके सहायक भी करते हैं।

राजनीति से ऊपर परिवार

उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को दो वर्ष से भी कम समय बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का प्रथम परिवार एकजुट होता नजर आ रहा है। सन 2017 के विधानसभा चुनाव के ऐन पहले पार्टी के पितृ पुरुष मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव पार्टी से अलग हो गए थे। बाद में उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली थी। हालांकि 2019 के आम चुनाव में इस नई पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई लेकिन उसने सपा के वोट बैंक में अवश्य सेंध लगाई थी। सपा की गठबंधन साझेदार बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली थी जबकि 2014 के चुनाव में पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। अभी हाल में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वह अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा के साथ गठजोड़ के लिए तैयार हैं और पाटी में कोई विवाद नहीं है। यादव परिवार के दोनों गुटों के बीच हाल में होली के त्योहार के अवसर पर भी नजदीकी देखने को मिली।

आपका पक्ष

सरकारी नौकरी पाना ही योग्यता नहीं

हाल में एक समाचार पत्र में विगत छह वर्षों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक 28 वर्षीय युवक द्वारा कथित आत्महत्या की खबर पढ़कर मन विचलित हो गया। यह कोई नया और इकलौता मामला नहीं है। अवसाद के कारण आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। अवसाद में जाने वाले युवाओं की बड़ी तादाद ऐसे अभ्यर्थियों की है जो सरकारी नौकरी पाने के लिए वर्षों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज के युवक स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने से पूर्व ही सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद तैयारी की गति में युवक की आर्थिक क्षमता के आधार पर परिवर्तन आता है। कुछ अभ्यर्थी निजी कंपनी में नौकरी करते हुए पढ़ाई जारी रखते हैं। वहीं आगे की मजबूत तैयारी के लिए कुछ साधन संपन्न युवक अपने अभिभावक की आर्थिक क्षमता के अनुसार तथा

निम्न मध्यम वर्गीय युवक कर्ज लेकर बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। सभी अभ्यर्थियों पर सफलता का दबाव रहता है। लेकिन सर्वाधिक दबाव उन निम्न मध्यम वर्ग वाले युवकों पर रहता है जिनके माता पिता उनसे खासी उम्मीद लगाए रहते हैं। ऐसे में काफी समय बाद भी जब सफलता नहीं मिल पाती तब अभ्यर्थी आत्मघाती कदम

युवाओं को सरकारी नौकरी का मोह त्याग कर निजी क्षेत्र में अवसर तलाशने चाहिए

उठाने पर विवश हो जाते हैं। युवकों के इस अवस्था तक पहुंचने के पीछे के कारणों की सूक्ष्म विवेचना की जरूरत है। युवकों में सरकारी नौकरी के मोह का एक प्रमुख कारण सामाजिक दबाव है। आज सरकारी नौकरी को योग्यता का प्रमाण पत्र तथा पैमाना मान लिया गया है। बढ़ती जनसंख्या के साथ अभ्यर्थियों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में सभी युवाओं को सरकारी नौकरी मिल पाए ऐसा असंभव है। समाज को अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। सरकारी नौकरी को योग्यता का एक मात्र पैमाना मानने से बचना होगा। निजी क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा हों। ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन यथाशीघ्र हो। युवाओं को भी अपनी क्षमता व योग्यता के अनुरूप लक्ष्य तय करके धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए।

ऋषभ देव पांडेय, जांजगीर

आयात पर असर, निर्यात पर नहीं

चीन में कोरोनावायरस के भय से विनिर्माण इकाइयों में छुट्टी के कारण भारत में चीन से आयात किए जा रहे सस्ते चीनी सामान अब महंगे हो गए हैं। वायरस के डर से लोग चीन का सामान खरीदने से परहेज कर रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक आदि उपकरण का चीन से आयात होता है जो इस वायरस से प्रभावित हो रहा है। हालांकि वायरस का भारत के निर्यात पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत के कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी महज 5 फीसदी है।

नेहा गुप्ता, गोरखपुर

भूल सुधार

गुरुवार 12 मार्च को बैंकों के बारे में प्रकाशित प्रथम पत्र की पांचवीं पंक्ति में पीएमसी का आशय पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक से है। असावधानीवश पीएमसी का पूरा नाम गलत प्रकाशित हो गया। त्रुटि के लिए खेद है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

संक्षेप में

कोयला खान नीलामी समयबद्ध हो : समिति

संसद की एक समिति ने कहा है कि वाणिज्यिक कोयले के उत्खनन प्रखंडों की नीलामी की प्रक्रिया और कोयला ब्लॉकों का आवंटन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खानों के आवंटन पर विचार कर रही है, जिससे घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। इसका पहला चरण चालू वित्त वर्ष में ही होने की उम्मीद है। कोयला एवं इस्पात पर स्थायी समिति की गुरुवार को संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि नीलामी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं और कोयला खानों का आवंटन समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। नीलामी प्रक्रिया के लिए 14 जनवरी को अंशधारकों के लिए परिचर्चा पत्र जारी किया गया। इस पर अंशधारक विचार विमर्श कर सकते हैं। *भाषा*

लुग्दी, कागज उद्योग के लिए विकास परिषद गठित

लुग्दी, कागज और संबंधित उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने एक 25 सदस्यीय विकास परिषद गठित की है। सरकारी गजट में छपी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने कागज उद्योग के लिए विकास परिषद कर दो वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों की नियुक्ति की है। जेके पेपर लिमिटेड के अध्यक्ष एएस मेहता को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। परिषद में भारतीय कागज विनिर्माण संघ के अध्यक्ष, भारतीय कृषि और पुनर्चक्रित कागज मिल संघ के अध्यक्ष, भारतीय न्यूजप्रिंट विनिर्माण संघ तथा अन्य को शामिल किया गया है। *भाषा*

कच्चे तेल, धातु में फिर से गिरावट

15 मिनट के अंदर बिटकॉइन में आई 1,000 डॉलर की गिरावट

राजेश भयानी
मुंबई, 12 मार्च

■ चांदी 3.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 44,280 रुपये प्रति किलोग्राम रहा

■ सोने का भाव 1.45 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 42726 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा

वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच जिंसों में आज भी कमजोरी बनी रही। धातुओं की गिरावट में तांबे का अहम योगदान रहा। तांबे को धातु में गिरावट का अगुआ माना जाता है, लेकिन हाल के सप्ताहों में धातुओं में आई गिरावट बुनियादी तौर पर आवश्यक नहीं दिख रही है।

वित्तीय बाजारों में कमजोर धारणा से क्रिप्टो मुद्राएं बुरी तरह से प्रभावित हुईं। बिटकॉइन 15 मिनट के अंदर 1,000 डॉलर गिरकर 6,000 के स्तर पर आ गई। कुछ दिन पहले यह मुद्रा लगभग 9,250 के आसपास कारोबार कर रही थी। इथेरियम, रिपल में भी गिरावट आई थी, हालांकि इनमें कुछ सुधार देखा गया। क्रिप्टो मुद्राओं पर नजर रखने वाले एक विश्लेषक ने कहा कि यह धारणा वित्तीय बाजारों में अन्य परिसंपत्ति वर्गों के अनुरूप है।

बाजार जानकारों का कहना है कि जब जब निवेशकों और कारोबारियों को मौका मिल रहा है, वे मुनाफावसूली कर रहे हैं। कॉमट्रेंड्ज रिसर्च में निदेशक ज्ञानशेखर त्यागराजन ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिर्फ भावनाएं काम कर रही हैं। फंडामेंटल और टेक्नीकल पीछे छूट गए हैं।' सभी वैश्विक बाजारों में विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में गिरावट की तर्ज पर एलएमई तांबा 2 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर 5,409 डॉलर प्रति टन पर आ गया, जो दिसंबर 2016 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है।

तांबे के अलावा जिन अन्य धातुओं में तेज गिरावट दर्ज की गई उनमें निकल (3.3 प्रतिशत) और जस्ता (1.2 प्रतिशत) शामिल रहे। इसके अलावा चांदी 3.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 44,280 रुपये प्रति किलोग्राम और सोने का भाव एमसीएक्स वायदा पर 1.45 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 42726 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

एक बाजार विश्लेषक के अनुसार, तांबे में शॉर्ट की रणनीति अपना चुके कई कारोबारियों ने मुनाफावसूली की है, जबकि ताजा शॉर्ट पोजीशन भी बनी हैं। अन्य धातुओं की तर्ज पर चांदी में भी गिरावट आई। हालांकि दोपहर के कारोबार में यह गिरावट सीमित हो गई। कच्चे तेल में गिरावट बरकरार रही। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,310 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

ज्ञानशेखर ने कहा, 'जब तक कोरोनावायरस से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए टीका बनाए जाने के संबंध में कोई ठोस रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक बाजार में अनिश्चितता बनी रह सकती है। बाजार में सुधार भी तेजी से हो सकता है। बाजार कंपनियों द्वारा ऐसे टीके की मार्केटिंग शुरू किए जाने की खबरों का इंतजार कर रहा है।' एल्गोरिदम कारोबारी भी बेहद सक्रिय हैं और रुझानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे ताजा टेक्नीकल सपोर्ट स्तर टूटने के बाद बिकवाली पर जोर दे रहे हैं।

अन्य परिसंपत्तियों की तरह कृषि जिंसों में भी गिरावट आई और ग्वारगम तथा ग्वारसीड वायदा एनसीडीईएक्स पर लोअर सर्किट के साथ बंद हुए, जबकि एमसीएक्स पर क्रूड पाम ऑयल वायदा 2.9 प्रतिशत तक टूटा।

कच्चे तेल की कीमतों का खाद्य तेलों (क्रूड पाम ऑयल, सोया तेल), ग्वारगम जैसी कई कृषिगत जिंसों के साथ प्रत्यक्ष संबंध रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष (कमोडिटी रिसर्च के प्रमुख) रवींद्र राव ने कहा, 'कच्चे तेल की कीमतों में जनवरी 2020 के शुरू से लगभग 50 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और जैव-ईंधन मिश्रण में खाद्य तेलों (पाम तेल और सोया तेल दोनों) का इस्तेमाल काफी घटा है।'

कोरोनावायरस : चीन को मूंगफली निर्यात में रुकावट

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 12 मार्च

फिर भी दाम में तेजी

- ■ चीन से नहीं मिल रहे नए ऑर्डर, वियतनाम से भी ऑर्डर हुए खत्म
- ■ निर्यात में कमी के बावजूद मूंगफली के दामों में नजर आ रही मजबूती
- ■ दामों में इजाफे के लिए व्यापारियों ने किसानों और स्टॉकिस्टों के पास स्टॉक की कमी को बताया जिम्मेदार

कोरोनावायरस का प्रकोप फैलने के कारण चीन के मूंगफली आयात में जोरदार तेजी आने के दो महीने बाद चीन से ऑर्डरों में रुकावट आ गई है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल और दिसंबर 2019 की अवधि में भारत का मूंगफली निर्यात आश्चर्यजनक रूप से 27 प्रतिशत बढ़कर 4,54,373 टन हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 3,57,795 टन था। हालांकि मूल्य के हिसाब से वृद्धि दर 41.64 प्रतिशत के साथ 48.9 करोड़ डॉलर रही, जबकि पिछले साल यह 34.6 करोड़ डॉलर थी।

निर्यात में ज्यादातर इजाफा नवंबर और दिसंबर 2019 की समयावधि के दौरान पिछले दो महीने में हुआ है। अमेरिका के साथ चीन के व्यापार युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा चीन पर 25 प्रतिशत का भारी आयात शुल्क लगाने और दुनिया में अन्य आपूर्तिकर्ता देशों की अनुपस्थिति के कारण ऐसा हुआ है।

देश के सबसे बड़े निर्यातकों में शुमार संजय शाह ने कहा, 'अप्रैल से अक्टूबर के बीच हमने 2,00,000 टन से कम मूंगफली निर्यात किया था। मांग में अचानक इजाफे से हम चीन और मुख्य रूप से सुदूर पूर्वी देशों में, शेष विश्व को करीब 2,50,000 टन मूंगफली का निर्यात कर पाए हैं। अमेरिका और सेनेगल जैसे अन्य देशों से आपूर्ति में कमी के कारण ऐसा हो पाया। कोरोनावायरस के प्रसार के कारण चीन में काम बंद होने से एक बार फिर चीन से ऑर्डर नदारद हो गए हैं। हमें जनवरी से मार्च तिमाही के बीच मूंगफली निर्यात में भारी कमी के आसार लग रहे हैं।'

किसानों के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि निर्यात में मंदी के बावजूद मूंगफली के दाम तेज रहे हैं। फरवरी की शुरुआत में मूंगफली के दाम गिरकर 57 रुपये प्रति किलोग्राम होने के बाद दामों में तेजी से सुधार हुआ है। जनवरी में दाम 59 रुपये प्रति किलोग्राम थे। फिलहाल दाम 60 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। इस तरह दामों में पिछले एक महीने के दौरान 5.3 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

व्यापारी दामों में इस तेजी का श्रेय किसानों और स्टॉकिस्टों के पास स्टॉक की अनुपलब्धता को दे रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह में संचयी दैनिक आवक में 30-40 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) के अध्यक्ष खुशवंत जैन ने कहा, 'चीन से अब नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। वियतनाम से भी ऑर्डर खत्म हो गए हैं। लेकिन ऑर्डर में यह गिरावट मुख्य रूप से कम आपूर्ति के बराबर है जिससे मूंगफली के दामों में मजबूती को समर्थन मिल रहा है। भारत पहले ही पिछले साल के मूंगफली निर्यात की मात्रा को पार कर चुका है। हमें उम्मीद है कि 1,50,000 टन मूंगफली के और निर्यात करने से इस साल देश का कुल निर्यात 6,00,000 टन हो जाएगा।'

हालांकि अधिक दामों का फायदा उठाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने स्टॉक की बिक्री करनी शुरू कर दी है।

बाजार की नब्ज टटोलने के लिए नेफेड अपनी मूंगफली बेचने के लिए कम मात्रा वाली निविदा लाया है। नेफेड ने वर्ष 2018 में इस मूंगफली की खरीद की थी। हालांकि कारोबारियों का कहना है कि उसके द्वारा बेची गई मूंगफली निर्यात के लिहाज से घटिया दर्जे वाली है, लेकिन इसका इस्तेमाल तेल निकालने और सीधे उपभोग के लिए किया जा सकता है।

25 फरवरी तक नेफेड ने मौजूदा सत्र के लिए प्रति क्विंटल 5,090 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की दर पर 3,655 करोड़ मूल्य की 7,18,019.35 टन मूंगफली खरीदी है।

भारी बारिश से चिंता में डूबे जालंधर के किसान

बीएस संवाददाता
जालंधर, 12 मार्च

पिछले सप्ताह की भारी बारिश के बाद बुधवार को लगातार हुई बारिश ने गेहूं किसानों को चिंता में डाल दिया है। जिले के कई इलाकों में गेहूं की फसल गिरने की खबर है। कुछ ही मिनटों की ओलावृष्टि में गेहूं के तने लुढ़क गए जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के पानी से भरे खेतों में अंकुरित अनाज की गुणवत्ता बिगड़ने की आशंका है।

किसानों ने दावा किया कि उन्हें प्रति एकड़ जमीन पर लगभग दो से तीन क्विंटल गेहूं को नुकसान हुआ है। गेहूं, मक्का, मटर और सरसों रबी की वे प्रमुख फसलें हैं जिन्हें नुकसान पहुंचने की खबर है। सुबह हवा के साथ शुरू हुई बारिश देर शाम तक जारी रही। करतारपुर के किसान दलजीत सिंह चार एकड़ जमीन के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हुई बारिश के बाद खेत पानी से भर गए थे और आज की बारिश ने चिंता बढ़ा दी है।

उन्होंने करीब एक क्विंटल गेहूं के नुकसान का दावा किया है। जिले के अन्य गांवों से भी इसी प्रकार के नुकसान की सूचना मिली है। लिधरन गांव के किसान गोपाल सिंह ने कहा कि फसल गिरने के बाद उन्हें अनाज काला पड़ने का डर है। बारिश के बाद गिरी फसल के लिए कंबाइन हार्वेस्टर मशीन भी मददगार नहीं होगी और अगर अनाज काला पड़ जाए, तो गेहूं की गुणवत्ता कम हो जाएगी जिससे दामों में गिरावट आएगी। कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान में ऐसा मौसम या तो खड़ी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है या उसकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। जिला कृषि अधिकारी नरेश कुमार गुलाटी ने कहा कि फसल के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण समय है और किसी भी व्यवधान से उपज में गिरावट आएगी। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में फिर से इस क्षेत्र में तूफान और बारिश आने की संभावना है।

राज्यों में गहराता कोरोना संकट

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठा रही है पर्याप्त कदम

भारत में कोरोनावायरस के 14 नए मामले सामने आने के बाद इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों, कॉलेजों और सिनेमाघरों को एहतियाती तौर पर 31 मार्च तक बंद रखने की गुरुवार को घोषणा की। केवल वे स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे जहां अभी परीक्षाएं जारी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और शीर्ष सरकारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला किया गया। दिल्ली में कोरोनावायरस का छठा मामला सामने आया है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि कोरोनावायरस का फैलना चिंता का विषय है और हम जिम्मेदारी पूर्वक इस पर प्रतिक्रिया दे रहे है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार का ध्यान कोरोना वायरस पर नियंत्रण करने में लगा हुआ है और इसने भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वे जहां हैं वहीं रहें और बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने विदेशी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया बल्कि कुछ सख्त कदम उठाए हैं।

...नियंत्रित नहीं हालात

- देश में कोरोनावायरस के संक्रमितों की तादाद बढ़कर 74 हो गई है
- दिल्ली में 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर
- विदेश मंत्री बोले, विदेशी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध नहीं बल्कि कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं
- ईरान में मरने वालों की तादाद 429

संक्रमण का बढ़ा दायरा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन 14 नए मामलों में से 9 मामले महाराष्ट्र से जबकि एक-एक मामला दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सामने आया है। वहीं एक विदेशी नागरिक भी इससे संक्रमित पाया गया है। मंत्रालय ने राज्यवार आंकड़े बताते हुए कहा कि दिल्ली में गुरुवार तक कोरोनावायरस के छह मामले सामने आ चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। कर्नाटक में चार, महाराष्ट्र में 11 और लद्दाख में तीन मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक-एक मामला सामने आया है। केरल में अब तक वायरस संक्रमण के 17 मामले सामने आ चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित 74 लोगों में 17 विदेशी नागरिक हैं। इनमें 16 इतालवी हैं। कैबिनेट सचिव ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा दो के प्रावधानों को लागू करना चाहिए ताकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी परामर्श लागू हो सकें। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि भारतीय डॉक्टरों की एक टीम गुरुवार को इटली के लिए रवाना होगी और वहां फंसे भारतीय छात्रों के लार के नमूने लेकर आएगी ताकि देश वापस लाने से पहले उनकी जांच की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ईरान में कोविड-19 फैलने की सूचना मिलने के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं।

देश में कोरोनावायरस संक्रमण के 14 नए मामले में से 9 महाराष्ट्र में सामने आए

वुहान में कम मामले

कोरोनावायरस से सवार्धिक प्रभावित चीन के वुहान में पहली बार संक्रमण का आंकड़ा आठ नए मामलों के साथ गिरकर एकल संख्या में पहुंच गया। हालांकि महामारी के विश्व में और भयावह होने की आशंका है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कोरोनावायरस के मद्देनजर यूरोप से अमेरिका आने वाले यात्रियों पर अगले 30 दिन तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इससे ब्रिटेन को छूट दी गई है।कोरोना वायरस से प्रभावित ईरान ने 1962 के बाद पहली बार आईएमएफ से कर्ज मांगा है। ईरान में कोरोनावायरस से 75 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 429 हुई। दुनियाभर में अब तक 4,600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। जबकि 1,26,000 से अधिक लोग इससे पीड़ित हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते विभिन्न देशों ने यात्रा प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। स्पेन में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 3000 हुए जबकि अभी तक 84 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सत्र निलंबित कर दिया गया है।

एजेंसियां

इंटरनेट की बढ़ेगी रफ्तार

गिरीश बाबू

कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने के डर से कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह रही हैं हालांकि कर्मचारी धीमे इंटरनेट स्पीड से जूझ रहे हैं। इस समस्या का हल करने के लिए केरल सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट स्पीड में 30-40 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने को कहा है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने भी मौजूदा नेटवर्क क्षमता के मुकाबले 30-40 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने पर अपनी सहमति दे दी है क्योंकि घर से काम करने की वजह से मांग में तेजी आई है।

केरल में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। यह बैठक मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा जारी निर्देश के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के सचिव ने बुलाई थी। यह फैसला आईटी संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होगा। सरकार के मुताबिक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वे मौजूदा हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरल में इंटरनेट मांग का एक बड़ा हिस्सा लोकल सर्वर ही पूरा करते हैं। कुल खपत के लिहाज से देखा जाए तो वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक कम है। इंटरनेट सेवा प्रदाता कहते हैं कि क्षमता में बढ़ोतरी इतनी मुश्किल नहीं है।

टिकट रद्द कराने को लेकर पसोपेश में दिखते यात्री

अनीश फडणीस और अरिंदम मजूमदार

दुनियाभर में कोरोनावायरस फैलने से विदेश यात्रा पर जाने वाले लोग पसोपेश में हैं। जो लोग पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं, उन्हें टिकट रद्द कराने पर नुकसान की चिंता है। वहीं जो लोग यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें बीमारी पड़ने या कुछ समय रोककर अलग रखे जाने के जोखिम का आकलन कर लेना चाहिए।

कोरोनावायरस के फैलने से दुनियाभर में यात्रा कारोबार में उठापटक मची हुई है। बहुत सी विमानन कंपनियां यात्रा टिकट को बदलने या रद्द करने के लिए वसूली जाने वाली फीस माफ कर रही हैं। भारत सरकार के सभी वीजा को स्थगित करने के फैसले और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के यूरोप और अमेरिका के बीच सभी उड़ानों को रोकने के फैसले से विमानन कंपनियां और यात्रा एजेंट अपनी उड़ानों की समय सारणी में बदलाव कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप के सीईओ राजेश मागोव ने कहा, 'हमारे कारोबार और पूरे उद्योग पर वास्तविक असर का आकलन लगाना मुश्किल हो गया है।' ट्रैवल पोर्टल यात्रा डॉट कॉम के अधिकारियों ने बताया कि ट्रिप प्रोटेक्शन प्लान में ग्राहक यात्रा को रद्द करने पर रिफंड हासिल कर सकते हैं। यात्रा की सह-संस्थापक और सीओओ सबिना चोपड़ा ने कहा, 'विदेश जाने की योजना बना चुके यात्रियों में से करीब 35 फीसदी लोगों ने टिकट रद्द कराने के बारे में पूछताछ की है। अगर हमारे यात्री अपनी आरक्षित टिकट को रद्द या कुछ समय टालना चाहते हैं तो हम उन्हें अपनी यात्रा की तारीख को स्थगित करने और वैकल्पिक तारीख बुक करने की सलाह दे रहे हैं।'

शेयर में गिरावट

सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए देश में यात्रा प्रतिबंध को सख्त बनाते हुए बुधवार को वीजा निलंबित करने का फैसला किया जिससे गुरुवार को देश की विमानन कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखी गई। गुरुवार सुबह के कारोबार में इंडिगो, स्पाइसजेट और बंद हो चुकी जेट एयरवेज के शेयरों में भारी गिरावट हुई। इस दौरान 30 शेयरों वाले सेंसेक्स सूचकांक में 2,000 अंकों से अधिक की गिरावट हुई। स्पाइसजेट के शेयरों में गुरुवार को करीब 19 फीसदी तक की गिरावट हुई जबकि कंपनी ने एकतरफ के किराये के लिए 13 डॉलर तक की पेशकश की। बुधवार को घरेलू बुकिंग में कमी की वजह से मुनाफे में कमी आने की आशंका से इंडिगो के शेयरों में 17 फीसदी तक की गिरावट देखी गई। वीजा को प्रतिबंधित किए जाने वाला यह कदम अप्रैल-जून के बीच गर्मियों में यात्रा के लिए व्यस्त समय से ठीक पहले आया है।

- टिकट कैंसिल कराने के लिए पूछताछ में 35 फीसदी का इजाफा
- यात्रा तारीख में बदलाव कराने पर शुल्क में छूट दे रहीं कंपनियां
- विमानन कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को भारी बिकवाली

अमेरिकाः यूरोप की उड़ानें रद्द

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के मद्देनजर यूरोप से अमेरिका आने वाले यात्रियों पर अगले 30 दिन तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इससे ब्रिटेन को छूट दी गई है। अमेरिका में इस वायरस के प्रकोप ने 37 लोगों की जान ले ली है और 1,300 से ज्यादा संक्रमित हैं। राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि नए नियम शुक्रवार आधी रात से प्रभाव में आएंगे और कई स्क्रीनिंग से गुजरने के बाद अमेरिकियों को अपने देश लौटने की छूट होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि उनके प्रशासन ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए जिस तरह के कदम उठाए हैं, वैसे ऐहतियाती उपाय करने में यूरोपीय संघ नाकाम रहा।

साथ में एजेंसियां

घर से काम करा रही हैं कंपनियां

समरीन अहमद और पीरजादा अबरार

देश में कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ने के साथ ही वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट और एमेजॉन जैसी शीर्ष ई-कॉमर्स कंपनियां भविष्य में काम को लेकर रणनीति बना रही हैं साथ ही अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह रही हैं। एमेजॉन इंडिया ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है जबकि फ्लिपकार्ट ने बेंगलूरु में अपने 10,000 कर्मचारियों को परीक्षण के तौर पर तीन दिन तक घर से ही काम करने को कहा है। फ्लिपकार्ट डिजिटल और वीडियो उपकरणों के जरिये दफ्तर से दूर से काम करने की तैयारियों की जांच भी कर रही है। ई-कॉमर्स कंपनी ने बेंगलूरु के अपने कॉरपोरेट मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बुधवार से ही तीन दिन तक घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है। फ्लिपकार्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'फिलहाल इसे परीक्षण योजना के तौर पर चलाया जा रहा है कि कोरोनावायरस संक्रमण फैलने पर घर से किस तरह काम किया जा सकता है।' उनका कहना है कि फ्लिपकार्ट पर लाखों विक्रेता निर्भर हैं और इससे करोड़ों की संख्या में ग्राहक जुड़े हैं ऐसे में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देकर भविष्य में महामारी के प्रकोप को देखते हुए खुद को तैयार रखने की योजना भी बनाई जा रही है। एक अधिकारी का कहना है, 'कंपनी ने ऐसे दबाव वाले वक्त में भी संचालन के लिए अपना तंत्र डिजाइन किया है लेकिन वे चाहते हैं कि कर्मचारी भी इस दबाव के लिए तैयार रहें। कंपनी ने इंजीनियरों को घर से काम करने की अनुमति दी है और साथ ही उन्हें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तथा बैंडविद्थ मुहैया कराया है जिसकी मदद से वे मुख्यालय की तरह ही घर से समस्या का समाधान कर सकेंगे।'

हैदराबाद और बेंगलूरु में दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की घटी तादाद

कंपनी बैठकों, साक्षात्कार आदि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल कर रही है और साथ ही इवेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम को टाल रही है। एक व्यक्ति ने बताया कि फ्लिपकार्ट समूह के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति खुद भी एक दिन में गूगल हैंगआउट पर कर्मचारियों का हालचाल जानने के साथ ही कीमत, आपूर्ति, तकनीकी स्थिति का जायजा लेते हैं।

वहीं एमेजॉन ने बेंगलूरु में अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की परीक्षण योजना शुरू कर दी है। कुछ टीमों को घर से लॉग-इन करने को कहा गया है ताकि कंपनी सिस्टम से जुड़ी तैयारियों की जांच का जायजा ले सके। एमेजॉन ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के खयाल रखते हुए एक वैश्विक राहत कोष बनाया है। एक सूत्र ने बताया, 'एमेजॉन का कोई भी कर्मचारी अगर कोरोनावायरस की जांच में पॉजिटिव रहता है या उसे अलग रखा जाता है तब उसे दो हफ्ते का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा ताकि वह काम पर अच्छी तरह वापसी कर सके।'

ई-कॉमर्स कंपनियां घर से काम कराने का कर रही हैं परीक्षण

बेंगलूरु के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के प्रवेश द्वार पर इन्फ्रारेड थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां एमेजॉन भी काम करती है। बेंगलूरु, कोच्चि और चेन्नई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अध्यक्ष विनीत वर्मा कहते हैं, 'हमारी टीमें हाई अलर्ट पर हैं और हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे यहां एक भी संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है।'

बी2बी यूनिकॉर्न उड़ान ने भी लोगों को घर से काम करने की सलाह दी है और अगर उन्हें दफ्तर में आना भी पड़े तो उन्हें फेसमास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खाद्य तकनीक कंपनी स्विगी ने अब तक घर से काम करने की कोई रणनीति नहीं बनाई है लेकिन इसने अपने कर्मचारियों को कहा है कि अगर वे घर से काम करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। बेंगलूरु में स्विगी के करीब 2,500 कर्मचारी है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे ने घर से काम करने की शुरुआत की है। फोनपे के एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर टीमों को अगले नोटिस तक घर से काम करने को कहा गया है।

देश में कोविड-19 के प्रभावित मरीजों की तादाद बढ़ने से दफ्तर जाने वालों कर्मचारियों में भय का माहौल है। एक कर्मचारी परिवहन प्रबंधन कंपनी मुवइनसिंक ने हजारों कर्मचारियों के रोजाना आवागमन के आंकड़े का जायजा लिया है जिससे कोरोनावायरस के असर का अंदाजा मिल सके। इसमें कहा गया है कि हैदराबाद और बेंगलूरु सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फिलहाल इसका ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा है। हैदराबाद में पिछले हफ्ते दफ्तर जाने वाले लोगों की तादाद में करीब 9 फीसदी की कमी आई जबकि बेंगलूरु में दफ्तर जाने वाले लोगों की तादाद लगातार घट रही है।

विदेशी क्रूज जहाज पर लगी रोक

भारतीय बंदरगाहों पर भी कोरोनावायरस संक्रमण का असर दिखना हो गया शुरू

अदिति दिवेकर

देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले फैलने की वजह से 11 मार्च से विदेशी क्रूज के आने पर रोक लगा दी गई है। वैश्विक स्तर पर क्रूज उद्योग में संकट के बावजूद घरेलू स्तर पर क्रूज सेगमेंट में हाल तक कोई हलचल नहीं दिख रही थी ऐसे में घरेलू क्रूज सेवा प्रदाताओं को यह उम्मीद थी कि इसका फायदा मिलेगा। लेकिन घरेलू सर्किट पर कुछ क्रूज को स्थगित कर दिया गया है। मुंबई पोर्ट के डिप्टी चेयरमैन यशोधन वानगे ने कहा, 'हमें जहाजरानी मंत्रालय से नोटिस मिला है कि देश में आने वाले सभी विदेशी क्रूज को 11 मार्च से रोक दिया जाए। इसकी वजह से हमें सीजन के आखिरी चरण में पहले की गई क्रूज की 15 बुकिंग को कैंसिल करना पड़ा है।'

मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा कि जिन अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाजों ने भारतीय बंदरगाहों पर 1 जनवरी 2020 से पहले आने की योजना की सूचना दी थी सिर्फ उन्हें ही इन बंदरगाहों पर आने की अनुमति दी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज या चालक दल का कोई सदस्य या यात्री अगर 1 फरवरी 2020 के बाद कोविड 19 प्रभावित देशों की यात्रा पर गया होगा उन्हें 31 मार्च तक देश के बंदरगाहों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।क्टूबर से शुरू होने वाले सीजन के लिए बुकिंग कैंसिल नहीं हुई थी बल्कि पहले से हुई 243 बुकिंग में से 220 क्रूज को मंगाया गया। फिलहाल जो 15 क्रूज को कैंसिल किया गया है जो बाकी बचे 23 प्री बुकिंग वाले क्रूज में ही शामिल है।

एस्सेल समूह के स्वामित्व वाला जलेश क्रूज केवल भारतीयों को ही लेकर आता था लेकिन गुरुवार की सुबह दुबई से यह खाली लौटा। जलेश क्रूज में 2,000 यात्रियों की क्षमता है जो केवल चालक दल के सदस्यों के साथ वापस लौटा जिनमें ज्यादातर भारतीय, कुछ अमेरिकी और कुछ फिलीपींस के नागरिक थे।

जलेश क्रूज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जर्गेन बेलोम ने बताया, 'हमारे 631 चालक दल सद्सय गैर-प्रतिबंधित क्षेत्रों से हैं जिन्होंने कभी जहाज छोड़ा ही नहीं। हालांकि उनका स्वास्थ्य जांच भी कराया गया है। पूरा चालक दल कोरोनावायरस जांच में नकारात्मक पाया गया।' जलेश क्रूज एक अंतरराष्ट्रीय जहाज है लेकिन वास्तव में यह घरेलू क्रूज है और इसी वजह से सरकार के मौजूदा कदम से इस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार ने विदेशी क्रूज को भारतीय बंदरगाहों पर आने पर प्रतिबंध लगाया है।

बेलम ने कहा, 'हमने सरकार के निर्देश के मुताबिक ही इस सीजन के बाकी बची 9 यात्राओं को मार्च के अंत तक के लिए टाल दिया है। अब तक हमने 31 मार्च के बाद के बारे में कुछ नहीं सोचा है और फिलहाल हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।' आमतौर पर जलेश के ग्राहकों में छुट्टियां मनाने वाले लोग, कॉरपोरेट समूह, शादी की योजना बनाने वाले और इवेंट आयोजक शामिल हैं जो भारतीय दर्शकों को नया अनुभव देते हैं।

जलेश क्रूज के अलावा, सी इगल क्रूज के स्वामित्व वाला एंग्रिया भी सक्रिय है जो मुंबई और गोवा के पर्यटकों को सेवाएं देती है। इस पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई देता है और फिलहाल यह सक्रिय है। देश में क्रूज सीजन अक्टूबर से मई तक चलता है और छुट्टियों की वजह से अंतिम महीन सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। देश में क्रूज के लिए मुंबई सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है और इसके बाद गोवा, मंगलूरु और कोच्चि का स्थान है।

वैश्विक स्तर पर क्रूज क्षेत्र में कोरोनावायरस महामारी का असर दिखने के बावजूद सीजन के शुरुआत से ही देश के क्रूज सेगमेंट में कारोबार अच्छा चल रहा था। घरेलू स्तर पर कोई बुकिंग कैंसिल नहीं हुई थी बल्कि बंदरगाहों पर ज्यादा पूछताछ की स्थिति थी। ऐसे में यह उम्मीद भी बन रही थी कि मौजूदा सीजन पिछले साल के मुकाबले अच्छा होगा।

न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के ट्रैफिक मैनेजर वाई आर बेलागल ने बताया, 'अब तक सबकुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक न्यू मंगलोर पोर्ट पर आने वाले 7 क्रूज को कैंसिल कर दिया गया है।' बुकिंग कैंसिल होने की वजह से पिछले साल के 26 जहाज के मुकाबले इस सीजन में केवल 19 क्रूज ही मिलेंगे। बेलागल ने कहा, मंगलूर पोर्ट को इस सीजन में बुकिंग कैंसिल होने की वजह से 1.75 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

- मुंबई पोर्ट पर आने वाले 15 क्रूज की योजना रद्द
- मंगलूर पोर्ट को बुकिंग कैंसिल होने से 1.75 करोड़ रुपये का नुकसान
- जलेश क्रूज ने मार्च के अंत तक 9 ट्रिप को स्थगित किया
- एंग्रिया क्रूज फिलहाल सक्रिय है

प्रभावितों को मुफ्त में मिलेगी ऑनलाइन शिक्षा

नेहा अलावधी और समरीन अहमद

भारत तथा विश्व की ऑनलाइन शिक्षण कंपनियां कोविड-19 महामारी के चलते स्कूल या उच्च शिक्षा के लिए चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की फीस को समाप्त कर दिया है। ऑनलाइन शिक्षण कंपनी कोर्सेरा ने कहा कि वह विश्व में कोरोनावायरस से प्रभावित प्रत्येक विश्वविद्यालय को 31 जुलाई तक अपने प्लेटफॉर्म पर चल रहे पाठ्यक्रमों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी।

कोर्सेरा में चीफ एंटरप्राइजेज ऑफिसर लेह बेल्स्की ने कहा, 'हम कोरोनावायरस से प्रभावित दुनिया के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में बिना किसी शुल्क के अपने पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों पर कोरोनावायरस के प्रभाव को न्यून करना है।'

कोर्सेरा पर पूरे विश्व में 4.8 करोड़ लोग पंजीकृत हैं और यहां स्पेशलाइजेशन, डिग्री तथा सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारत में इस प्लेटफॉर्म पर 50 लाख लोग पंजीकृत हैं और प्रत्येक महीने एक लाख से अधिक लोग इससे जुड़ रहे हैं। 3,800 से अधिक कोर्स तथा 400 स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अपने छात्रों की जानकारियों के साथ साइन-अप कर सकती हैं।

इसी तरह, भारतीय एजुकेशन-तकनीक क्षेत्र की कंपनियां भी नोवल कोरोनावायरस से प्रभावित छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन कक्षाएं तथा पाठ्यसामग्री उपलब्ध करा रही हैं। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया है। एजुकेशन-तकनीक क्षेत्र की कंपनी बायजू का भी कहना है कि वह अप्रैल के अंत तक स्कूल के छात्रों को अपने ऐप पर उपलब्ध संपूर्ण पाठ्यक्रम तक पहुंच प्रदान करेगी। भारत के कुछ राज्यों, जैसे केरल, कर्नाटक तथा देश की राजधानी नई दिल्ली ने पहले ही स्कूलों तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों को बंद करने की घोषणा कर दी है। एक अन्य प्लेटफॉर्म अनअकेडमी का कहना है कि वह यूपीएससी, बैंकिंग और रेलवे समेत विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर 20,000 के करीब लाइव कक्षाएं उपलब्ध कराएगी। कंपनी का दावा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर 30 से अधिक परीक्षाओं के लिए 10,000 शिक्षक, 1.3 करोड़ पंजीकृत सबस्क्राइबर्स हैं। बेंगलूरु स्थित 'एजुकेशनल इनशिएटिव्स' भी सभी छात्रों को 60 दिन तक 'माइंडस्पार्क' मुफ्त में उपलब्ध कराएगी जिससे कोरोनावायरस के चलते स्कूल बंद होने से उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। 'माइंडस्पार्क' कृत्रिम मेधा (एआई) तकनीक युक्त गणित का प्रोग्राम है जिससे बच्चों को गणित पढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है।